▪ RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 14 ▪ अंक - 16 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 07-08-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 अशोक गहलोत ने डांगावास हत्याकांड में फैसले को बेहद चिंताजनक बताया

6 'धुरंधर' पर अखिलेश की नाराजगी के सियासी मायने

7 मॉडलिंग क्या होती है, ये भी नहीं जानती थीं : तनुश्री चक्रवर्ती

## फर्स्ट टेक

### बांग्लादेश में 20 अगस्त को होगा राष्ट्रपति चुनाव

ढाका/भाषा। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि देश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को कराया जाएगा। सत्ता से अपदस्थ की गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे समय से सहयोगी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपना कार्यकाल पूरा होने से दो साल पहले ही 24 जुलाई को पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति चुनाव अपरिहार्य हो गया था। निर्वाचन आयोग सचिवालय के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बृहस्पतिवार को बताया कि मतदान 20 अगस्त को अपराह्न 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जातीय संसद के सत्र कक्ष में होगा। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, अहमद ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद से बातचीत के बाद की गई। हाफिज उद्दीन अहमद संविधान के तहत 90 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं।

### नौका दुर्घटनाग्रस्त, श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को बचाया

कोलंबो/भाषा। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बृहस्पतिवार को श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यह दुर्घटना श्रीलंका के उत्तरी तट के पास पाक जलडमरूमध्य में स्थित डेल्फ़्ट द्वीप (जिसे नेदुंथिवु भी कहा जाता है) की तटीय मूंगा चट्टान (कोस्टल रीफ) के पास हुई। श्रीलंका नौसेना के अनुसार, यह नौका बुधवार देर रात अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करके श्रीलंका के जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई थी और कथित तौर पर चट्टान से टकराकर वहां फंस गई।

### मेटा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, एल्गोरिद्म और भारतीय कानूनों के पालन पर सरकार सख्त

नई दिल्ली/भाषा। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा के अधिकारियों से बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन भारत सरकार के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान इंस्टाग्राम के कंटेंट सुझाव संबंधी एल्गोरिद्म और भारतीय कानूनों के अनुपालन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों का संचालन करने वाली कंपनी मेटा के अधिकारियों ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वह डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और बॉट खातों से निपटने के लिए काम कर रही है।

07-07-2026 सूर्यास्त 6:45 बजे | 08-08-2026 सूर्योदय 6:08 बजे

| BSE | NSE |
|---|---|
| 78,581.00 ( +152.05 ) | 24,624.65 (+9.75) |

| सोना | चांदी |
|---|---|
| 15,832 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | 250,000 रु. प्रति किलो |

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

### ये जो पब्लिक है

अब आत्म मुग्धता प्रवंचना का,
कैसा है यह अजब दौर।
खुद को सब समझे साहुकार,
दूजों को कहते चोर-चोर।
वादे इनके तो हैं सपने,
उनकी बातें हैं सिर्फ शोर।
सच तो होता सूरज जैसा,
जनता करती है सदा गौर।।

तेजपाल दोषी करारा, 10 साल की सजा

## उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को अनुचित बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए बृहस्पतिवार को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को अनुचित करार दिया। उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि निचली अदालत इस धारणा का शिकार हो गई कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को ''आदर्श पीड़िता'' होना चाहिए और उसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की पीठ ने 81 पृष्ठों के फैसले में बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता को कठघरे में खड़ा करने और उसके निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि निचली अदालत ने जिरह के दौरान बचाव पक्ष को उसे ''परेशान और अपमानित'' करने दिया। उच्च न्यायालय ने तेजपाल को बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़िता ने सत्य बयान दिए और अभियोजन पक्ष ने अपना मामला हर तरह के ''संदेह से परे'' साबित किया।

## झारखंड परीक्षा आंदोलन 13वें दिन भी जारी

रांची/भाषा। झारखंड में भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गया और इस दौरान छह प्रदर्शनकारी अनशन पर हैं। वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार के साथ बातचीत करके गतिरोध दूर करने के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित किया। प्रदर्शन की गूंज बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा तक पहुंची, जहां मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने परिसर में नारेबाजी करके छात्रों की मांगों का समर्थन किया। यह प्रदर्शन 25 जुलाई को यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 'जे पी एस सी-जे एस एस सी रिफॉर्म्स मंच' के बैनर तले शुरू हुआ था और हाल के वर्षों में राज्य के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बन गया है। जे पी एस सी-जे एस एस सी रिफॉर्म्स मंच के एक पदाधिकारी ने कहा, सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव के जवाब में हमने 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया है, जिसमें आठ छात्र, दो विशेषज्ञ और एक अधिवक्ता शामिल हैं। सरकार के साथ बातचीत का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुधवार को दिए गए बयान के एक दिन बाद लिया गया।

विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा

# चर्चा के लिए उपलब्ध हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह : किरेन रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

> "विपक्ष सदन का कामकाज रोक रहा है, जबकि आरोप यह लगा रहा है कि सरकार बहस से बच रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही संसद में मौजूद रहते हैं और शाम को ही जाते हैं।

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे दिन संसद में मौजूद रहते हैं और चर्चा के लिए उपलब्ध रहते हैं। रीजीजू ने कहा कि संसद में गतिरोध के बावजूद विधायी कामकाज जारी है और विधेयक पारित किए जा रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अवरुद्ध बनी हुई है।

संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए रीजीजू ने कहा कि विपक्ष सदन का कामकाज रोक रहा है, जबकि आरोप यह लगा रहा है कि सरकार बहस से बच रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही संसद में मौजूद रहते हैं और शाम को ही जाते हैं।एस्स्ल

विपक्ष ही सदन का कामकाज नहीं चलने दे रहा है और बाहर नारे लगा रहा है। यह सही नहीं है। रीजीजू ने कहा कि सरकार ने सदन में कामकाज करने और विधेयक पारित कराने का काम जारी रखा है, खासकर राज्यसभा में, जहां विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बावजूद चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, ''हम विधेयक पारित कर रहे हैं और सदन का कामकाज चला रहे हैं। राज्यसभा में उचित चर्चा के बाद विधेयक पारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस और उसके एक-दो सहयोगी दल भले ही सदन से वॉकआउट कर रहे हों या हंगामा कर रहे हों, लेकिन सदस्य चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं।'' संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया कि लगातार हो रहे व्यवधान से सरकार के बजाय कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर उसके पहली बार सांसद बने नेताओं को संसद में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए पहले ही 'क्रांतिकारी' कदम उठाए हैं और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर बार-बार विरोध-प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, ''यह मुद्दा खत्म हो चुका है। देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक पर क्रांतिकारी फैसले लिए हैं।

## नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बृहस्पतिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की तथा दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया, ''प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर बातचीत की। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।'' पश्चिम एशिया में संघर्ष बिना किसी स्थायी समाधान के पांच महीने से अधिक समय से जारी है।

ईरान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में इजराइल के दो सैनिक मारे गए हैं। यह जलडमरूमध्य वैश्विक पोत परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले, दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस जलमार्ग से होकर गुजरता था।

## सरकार ने संवेदनशील ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय-सीमा घटाकर दो घंटे की

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सोशल मीडिया मंचों के लिए संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय-सीमा 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दी है। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, इस साल 10 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 में संशोधन किए गए थे ताकि कृत्रिम रूप से तैयार जानकारी जैसे डीपफेक और एआई-जनित सामग्री से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए नियामकीय ढांचे को मजबूत किया जा सके। बयान में कहा गया, इसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को और सख्त किया गया है। वैध कारणों के साथ सरकार या अदालत के आदेश मिलने पर अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। वहीं शिकायत निवारण की समय-सीमा (अश्लीलता एवं प्रतिरूपण जैसे विशेष मामले) 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दी गई है। आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख सोशल मीडिया मंचों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे उचित तकनीकी उपाय, जैसे स्वचालित उपकरण या अन्य व्यवस्था लागू करें ताकि बलात्कार और बाल यौन शोषण से संबंधित या पहले हटाई जा चुकी समान सामग्री की पहचान सक्रिय रूप से की जा सके।

## 'गोबरधन' के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन में तेजी लाने के लिए बृहस्पतिवार को 23,731 करोड़ रुपये की एक राष्ट्रीय एकीकृत योजना को मंजूरी दी।

यह योजना आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को मजबूत करने के लिए कृषि एवं शहरी कचरे के उपयोग पर आधारित है। सरकार ने एक बयान में कहा कि 'गोबरधन' (जैविक संसाधनों से धन सृजन) योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 के बीच लागू की जाएगी।

इसका लक्ष्य सुनिश्चित खरीद, विनियमित मूल्य, पूंजी सब्सिडी, पाइपलाइन अवसंरचना और वित्त तक आसान पहुंच के जरिये घरेलू सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना है।

रैली

कोलकाता में 'हीरोशिमा दिवस' के अवसर पर विश्व शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश देते हुए शांति रैली निकालते 'पश्चिम बंग विज्ञान मंच' के सदस्य।

# संवाद का एक वैध तरीका है विरोध प्रदर्शन : मोहन भागवत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध तरीका है, लेकिन इसका मकसद विभाजन पैदा करने के बजाय आम सहमति बनाना होना चाहिए।

भागवत ने मुंबई में 'इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स' (आईआईएमयूएन) के 15वें वर्षगांठ कार्यक्रम में में 'जेन-जी' और 'जेन अल्फा' के लगभग 2,000 सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, ''विरोध प्रदर्शन भी बातचीत का एक तरीका है। लोकतंत्र में, विरोध प्रदर्शन आम सहमति बनाने का एक जरिया है। अलग-अलग विचार एक साथ आते हैं और चर्चा के बाद आम सहमति बनती है।'' उन्होंने कहा, ''अगर विभिन्न कारणों से बातचीत के जरिए

चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो लोग आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन इन सबका मकसद आम सहमति बनाना है, न कि विभाजन पैदा करना। जेन-जी की शिकायतें जायज़ हैं और मुझे उनकी ईमानदारी पर भरोसा है।''

भागवत के इस संवाद को आरएसएस की ओर से 'जेन-जी' और 'जेन अल्फा' तक पहुंचने की सबसे अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह कोशिश कॉरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के उस विरोध-प्रदर्शन के बाद हो रही है, जो नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुआ था तथा उसके फलस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था।

भागवत ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर जताई जा रही चिंताएं जायज हैं। उन्होंने कहा कि संवाद हमेशा पहला कदम होना चाहिए। भागवत ने कहा, ''बातचीत होनी चाहिए। अगर बातचीत से काम न बने तो आगे क्या किया जाए, इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।'' सरसंघचालक ने कहा कि जेन-जी अपनापन और सम्मान के साथ-साथ 'तार्किक जवाब' भी चाहता है, जबकि पिछली पीढ़ियां बिना सवाल किए बड़ों की बात मान लेती थीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना इसके नुकसानदेह असर का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज को आत्म-अनुशासन विकसित करना चाहिए और ऑनलाइन किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जब तक लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक सिर्फ़ नियम-कानून काम नहीं आएंगे।

# विजय सरकार का पहला कृषि बजट पेश, अल नीनो से निपटने की कार्ययोजना तैयार

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 58,374 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण, मिट्टी की उर्वरता, दाल-तिलहन एवं कपास उत्पादन बढ़ाने के मिशन समेत कई नई योजनाओं की घोषणा की गई। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि सुपर अल नीनो के कारण राज्य के 12 जिलों पर अधिक असर पड़ने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।

तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार का पहला कृषि बजट पेश करते हुए राज्य के कृषि मंत्री आर विनोद ने कहा कि यह बजट विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसे किसानों की आजीविका और कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं, विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने बजट को किसानों के लिए निराशाजनक बताते हुए इसकी आलोचना की। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने भी बजट पर सवाल उठाए।

मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में फसल उत्पादन के लिए किसानों की अल्पकालिक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि से जुड़े अन्य कार्यों, जैसे मधुमक्खी पालन, के लिए 3,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पात्र किसानों के फसल ऋण माफी के लिए सरकार अब तक कुल 5,267 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसमें पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त में 3,000 करोड़ रुपये, तीसरी किस्त में 1,820 करोड़ रुपये और चौथी किस्त में 347 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सुपर अल नीनो का उल्लेख करते हुए विनोद ने कहा कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की कार्ययोजना के आधार पर राज्य में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मौसमी घटना के कारण पूरे देश में, विशेषकर कुरुवई फसल मौसम (जून-जुलाई और अगस्त की शुरुआत) के दौरान गंभीर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 12 जिलों के अधिक प्रभावित होने का अनुमान है। इसके मद्देनजर सभी जिलों के लिए तैयार कृषि आकस्मिक योजना जिलाधिकारियों को भेज दी गई है ।

# कोच्चि आ रहे विमान का आपातकालीन निकास खोलने का प्रयास करने के आरोप में यात्री गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि/भाषा। कुआलालंपुर से कोच्चि आ रहे एक विमान का आपातकालीन निकास खोलने का कथित प्रयास करने और सह-यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों को धमकी देने के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यात्री पर आपातकालीन निकास की खिड़की को क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप है। उसने बताया कि आरोपी की पहचान जमशीर अथानिक्कल के रूप में हुई है। वह बुधवार को कुआलालंपुर से कोच्चि आ रही बैटिक एयर की उड़ान संख्या ओडी231 में सवार था। प्राथमिकी के अनुसार, घटना विमान के हवा में होने के दौरान रात साढ़े नौ बजे से 11 बजकर पांच मिनट के बीच हुई।

इसमें आरोप लगाया गया है कि यात्री ने विमान के आपातकालीन निकास को जबरन खोलने का प्रयास किया, उसकी खिड़की को नुकसान पहुंचाया और सह-यात्रियों को धमकाया। पुलिस ने बताया कि चालक दल के सदस्यों ने हस्तक्षेप कर यात्री को काबू में कर लिया। उसने बताया कि कोच्चि में बैटिक एयर के सुरक्षा प्रभारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और बृहस्पतिवार तड़के उड़ान के पहुंचने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक धमकी के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3), सुरक्षा निर्देशों के उल्लंघन के लिए विमान अधिनियम की धारा 11ए और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है।

कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) के अनुसार, उड़ान के बृहस्पतिवार तड़के करीब दो बजकर 40 मिनट पर कोच्चि पहुंचने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने आरोपी यात्री को हिरासत में लिया और बाद में उसे नेदुंबस्सेरी पुलिस थाने को सौंप दिया। सीआईएएल के बयान के अनुसार, जमशीर पलक्कड़ जिले के कूट्टनाड का रहने वाला है। आरोप है कि उसने उड़ान के दौरान विमान की एक खिड़की को नुकसान पहुंचाया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

# आरबीआई ने टाटा संस को उच्च श्रेणी वाली एनबीएफसी की सूची में बरकरार रखा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को टाटा संस को उच्च श्रेणी की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की सूची में बरकरार रखा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि होल्डिंग कंपनी को सूची में शामिल किए जाने से उसके एनबीएफसी पंजीकरण को लौटाने के लंबित आवेदन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने आकार आधारित विनियमन रूपरेखा के तहत उच्च श्रेणी की एनबीएफसी की नवीनतम सूची जारी की। इसमें 17 कंपनियां शामिल हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं और मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) पर अधिक कड़े नियामकीय प्रावधान लागू होते हैं।

आरबीआई ने कहा, ''सूची में टाटा संस प्राइवेट लि. को शामिल किया जाना उसके पंजीकरण रद्द करने के आवेदन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। फिलहाल इस आवेदन की जांच की जा रही है।'' चार सौर अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को पहली बार 2022 में उच्च श्रेणी की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण के तहत कंपनी को कड़े नियामकीय नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें भविष्य में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना तथा सख्त संचालन व्यवस्था, पूंजी और खुलासा आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। यह व्यवस्था तबतक रहती है जब तक कि वह अपनी संरचना में बदलाव नहीं करती। इसके बाद टाटा संस ने वित्तीय कारोबार में अपनी हिस्सेदारी कम करने और समूह के कुछ हिस्सों के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए। कंपनी ने आरबीआई के वर्गीकरण से छूट देने का अनुरोध भी किया था। कंपनी ने उधारी कम करने और अपने वित्तीय सेवा कारोबार के पुनर्गठन के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें वित्तीय परिचालन को अपनी मुख्य निवेश गतिविधियों से अलग करना शामिल है।

# अतीक अहमद के बेटे की झांसी में सड़क हादसे में मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

झांसी/भाषा। माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की बृहस्पतिवार को झांसी जिले में एक सड़क हादसे में मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस घटना में कार सवार तीन अन्य लोग घायल हो गये, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अरविंद कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी तेज गति से गुजर रही कार (एसयूवी) बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने संवाददाताओं को बताया कि इस हादसे की सूचना पुलिस को सुबह साढ़े 10 बजे मिली। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई। मूर्ति ने बताया कि हादसे में घायल कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि वे सभी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिये भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। मूर्ति ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कार की गति बहुत तेज थी। उन्होंने कहा, घायल यात्रियों में से एक ने हमें बताया कि गाड़ी बहुत तेज गति से गुजर रही थी और डिवाइडर से टकराने से पहले बेकाबू हो गई थी।

दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में सवार रहे अबान के घायल दोस्त मोहम्मद उमर ने संवाददाताओं को बताया कि वे अबान के भाई से मिलने झांसी जेल जा रहे थे तभी कार बेकाबू हो गयी और यह हादसा हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी।

माना जा रहा है कि अबान के शव को प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, जहां उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी दफनाया गया था।

सूत्रों के मुताबिक अबान अतीक अहमद के पांच बेटों में सबसे छोटा और अहजम का जुड़वां भाई था। साथ ही पांच भाइयों में से उमर और अली अभी उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जेलों में बंद हैं।

अहमद का एक और बेटा असद अप्रैल 2023 में झांसी के पास पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। वह वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की हत्या के मामले में वांछित था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पत्रकार बनकर पहुंचे तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जा रही थी।

# आसाराम को अपनी पसंद का प्रशिक्षित देखभालकर्ता रखने की अनुमति, फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के 2013 के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया लेकिन उसे चौबीसों घंटे सहायता के लिए अपनी पसंद का प्रशिक्षित देखभालकर्ता (केयरटेकर) रखने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाली आसाराम की याचिका को लंबित रखा। पीठ ने उसे यह छूट दी कि स्वास्थ्य बिगड़ने पर वह मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आसाराम ने न्यायालय से यह तथ्य छिपाया कि उसके वकील ने पैरोल के लिए आवेदन किया था। आसाराम के वकील ने कहा कि पैरोल के लिए आवेदन काफी पहले किया गया था और वह स्वास्थ्य आधार पर नहीं था। इससे पहले, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल देते हुए कहा था कि राज्य सरकार उसके पैरोल आवेदन को खारिज करने के अपने फैसले को उचित नहीं ठहरा सकी। उच्च न्यायालय ने जोधपुर केंद्रीय कारागार में बंद 85 वर्षीय आसाराम को यह राहत जेल में बिताई गई अवधि और पहले अंतरिम रिहाई के दौरान उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए दी थी। उच्चतम न्यायालय को पहले बताया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञों के अनुसार, आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसे चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को एम्स को आसाराम के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के 2013 के मामले में आसाराम की दोषसिद्धि और उसे सुनाई गई उम्रकैद की सजा को 27 मई को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आसाराम की याचिका पर 30 जून को राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था।

# डाक विभाग श्री पद्मनाभ मंदिर पर विशेष लिफाफा जारी करेगा

तिरुवनंतपुरम/भाषा। डाक विभाग 10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को समर्पित एक स्थायी चित्रात्मक मुहर और एक प्रीमियम विशेष लिफाफा जारी करेगा। विभाग ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इस विशेष स्थायी मुहर का मकसद मंदिर की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना और उसे बढ़ावा देना है। उसने कहा कि ये यादगार लिफाफा और मुहर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक से जुड़े डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यादगार चीज़ें होंगी। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 10 अगस्त को यहां एक कार्यक्रम में ये यादगार डाक-सामग्री जारी करेंगे। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान केरल के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी वाले पोस्टकार्ड भी जारी किए जाएंगे। श्री महा विष्णु को समर्पित यह मंदिर उनके 'अनंतशयन' रूप के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। यह तीर्थस्थल अपनी धार्मिक महत्ता, अनोखी वास्तुकला और प्राचीन परंपराओं की वजह से सदियों से श्रद्धालुओं, इतिहासकारों और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। मंदिर के तहखानों में बेशकीमती खजाने मिलने के बाद इसे दुनिया भर में पहचान मिली और अक्सर इसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है।

# कॉजपा अगले महीने क्या 'बोलती पब्लिक' मुहिम शुरू करेगी : दीपके

छत्रपति संभाजीनगर/भाषा। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बृहस्पतिवार को कहा कि कॉजपा अगले महीने देशभर में लोगों से संवाद करने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए क्या ''बोलती पब्लिक'' मुहिम शुरू करेगी। वह महाराष्ट्र में अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर में कॉजपा की कोर टीम' की बैठक खत्म होने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कोर टीम बुधवार से ही दीपके के घर पर वार्ता कर रही थी।

दीपके ने कहा, ''इस क्या 'बोलती पब्लिक' मुहिम के दौरान हमें पता चलेगा कि देश के मौजूदा हालात के बारे में लोग क्या सोचते हैं और उन्हें किन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।'' केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन की सबसे बड़ी कामयाबी बताते हुए दीपके ने कहा, पिछले 10-12 साल में इस सरकार ने लोगों के मन में जो डर पैदा किया था, वह अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, ''अब लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज उन्होंने एक व्यक्ति का इस्तीफा मांगा है। कल वे अन्य व्यक्तियों का भी इस्तीफा मांगेंगे।'' दीपके ने कहा, ''कॉजपा विकसित भारत के लिए बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित (जवाहरलाल) नेहरू की दृष्टि के अनुसार काम करेगा।''

# कर्नाटक ने कबानी नदी पर बैराकुप्पा पुल निर्माण के लिए दी मंजूरी : केरल के मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। कर्नाटक सरकार ने केरल-कर्नाटक सीमा पर कबानी नदी पर लंबित बैराकुप्पा पुल के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

केरल के लोक निर्माण मंत्री पी ए बशीर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि उन्हें बेंगलुरु में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के साथ हुई चर्चा के बाद यह मंजूरी मिली।

बशीर ने कहा कि दशकों से लंबित इस परियोजना को कर्नाटक सरकार ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित अंतरराज्यीय पुल केरल के वायनाड जिले के पेरिक्कल्लूर को कर्नाटक के कोडागु जिले के बैराकुप्पा से जोड़ेगा। इससे दोनों राज्यों के बीच सड़क संपर्क का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। मंत्री के अनुसार, इस पुल की आधारशिला 36 वर्ष पहले रखी गई थी। इसके बाद 15 मार्च, 2002 को तत्कालीन केंद्रीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। उन्होंने बताया कि केरल की ओर संपर्क मार्ग का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि परियोजना के पूरा होने के लिए अब कर्नाटक की ओर संपर्क मार्ग का निर्माण आवश्यक है।

बशीर ने कहा कि उन्होंने पहले कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर उसकी ओर संपर्क मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ताजा एनओसी परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

# केरल उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों पर हमला मामले में छह और आरोपियों को जमानत दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने इस साल मई में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास पर छापेमारी के लिए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमला करने के आरोपी छह और लोगों को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने मामले में रेवंत, आर. उन्नीकृष्णन, उन्नी डीएस, आईपी बीनू, डीबी नायर और दिनकर को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच लगभग पूरी हो चुकी है, आरोपियों का कोई गंभीर अपराध का पिछला रिकॉर्ड नहीं है और पीड़ितों को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

वहीं, न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने कहा कि केस डायरी देखने से पता चलता है कि चारों पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं और (प्रथम दृष्टया) ये उनकी ओर से पहले से सोच-समझ कर किए गए आपराधिक कृत्य का संकेत हैं। उच्च न्यायालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में 17 अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी और इनमें से एक आरोपी को अधीनस्थ अदालत से जमानत मिली थी। इस मामले में छह और लोगों को जमानत मिलने के साथ ही अबतक 24 आरोपियों को राहत मिल गई है। इस मामले में पुलिस ने 300 चिह्नित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ईडी के अनुसार इनमें से कई आरोपियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है या वे फरार हैं। अदालत ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके जमा करने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कई शर्तें भी लगाईं और कहा कि आरोपियों को जांच में पूरा सहयोग करना होगा, हर शनिवार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच और जरूरत पड़ने पर भी जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। साथ ही, तिरुवनंतपुरम के छावनी थाना क्षेत्र में जाने से बचना होगा और संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जमा करने होंगे।

अदालत ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि जमानत पर रहने के दौरान वे इस तरह का कोई अपराध न करें, अभियोजन पक्ष के गवाहों से किसी भी तरह से संपर्क न करें, उन्हें प्रभावित या डराएं-धमकाएं नहीं, और अधीनस्थ अदालत की अनुमति के बिना राज्य से बाहर न जाएं। ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि 27 मई को उसके अधिकारियों पर हुए हमले को सामान्य कानून-व्यवस्था की घटना या अचानक हुआ जन-विरोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह हमला कई घंटों तक चली छापेमारी की कार्रवाई के बाद हुआ था।

# केकेआर 1.2 अरब यूरो के मूल्यांकन पर मेडिकवर इंडिया का अधिग्रहण करेगी

नई दिल्ली/भाषा। वैश्विक निवेश कंपनी केकेआर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और जांच सेवा प्रदाता कंपनी मेडिकवर एबी के भारतीय अस्पतालों के परिचालन का 1.2 अरब यूरो के मूल्यांकन पर अधिग्रहण करेगी। हालांकि केकेआर ने इस सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मेडिकवर इंडिया के अल्पांश शेयरधारकों को परामर्श दे रही कानूनी फर्म ट्राइलीगल ने कहा कि इस सौदे में मेडिकवर इंडिया का मूल्यांकन 1.2 अरब यूरो आंका गया है। केकेआर ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2017 में स्थापित मेडिकवर इंडिया दक्षिण एवं पश्चिम भारत में 24 अस्पतालों और लगभग 4,800 बिस्तरों वाले अस्पतालों के नेटवर्क का संचालन करती है।

# प्रशांत किशोर ने मुंबई में सुनेत्रा पवार से मुलाकात की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। बिहार में हाल में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जीत दर्ज कर चौंकाने वाले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पदाधिकारी संजय खोडके ने बताया कि राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने किशोर ने राकांपा प्रमुख सुनेत्रा पवार से दक्षिण मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास 'देवगिरी' में मुलाकात की।

राकांपा नेता ने किशोर और पवार के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं की चुनावी जीत की रणनीति तैयार कर चुके किशोर की इस साल जनवरी में बारामती में एक विमान दुर्घटना में सुनेत्रा पवार के पति और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनसे यह दूसरी मुलाकात है। कुछ महीने पहले हुई पहली मुलाकात के बाद उनके बेटे और राकांपा नेता पार्थ पवार ने कहा था कि किशोर उनके परिवार के परिचित हैं। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सीट खाली करने के कारण हुआ था। भाजपा ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें किशोर ने हराया।

# मुझे राजनीति का शिकार बनाया गया : तेजपाल

पणजी/भाषा। 'तहलका' पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के दुष्कर्म मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि वह राजनीति का शिकार है और उसे गत 13 सालों से उसकी पत्रकारिता की वजह से निशाना बनाया जा रहा है।

तेजपाल ने यह भी आरोप लगाया कि उसका करियर और उसकी किताबों की छपाई भी रोक दी गई है। उसने फैसला आने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा और साथ ही भरोसा जताया कि अंतत: सच सामने आएगा। तेजपाल ने कहा, हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हमें लगता है कि यह आदेश गलत है। हम इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएंगे।'' तेजपाल ने आरोप लगाया कि उसे तहलका' के लिए गए काम की वजह से निशाना बनाया गया है। उसने कहा, ''हम निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय जाएंगे। हमें कोई शक नहीं है कि पिछले 13 सालों से 'तहलका' में मेरे काम की वजह से ही वे मेरे पीछे पड़े हैं। सुनवाई अदालत में सात साल तक मुकदमा लड़ने के बाद हम बरी हो गए थे, लेकिन वे फिर से हमारे पीछे पड़ गए हैं।'' 'तहलका' के पूर्व संपादक ने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफबोलने या लिखने वालों को निशाना बनाया जा रहा था। उसने कहा, जो लोग उनके साथ हैं, वे बरी हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ पत्रकारिता की है या उनके खिलाफ कुछ कहा है, वे ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। पिछले 12 सालों में ऐसे कई मामले देखे जा सकते हैं जिनमें उन्होंने अपने विरोधियों को फंसाया है।

# जरांगे ने जानबूझकर कुनबी प्रमाणपत्र रद्द किए जाने का दावा किया

**बावनकुले ने आरोपों को गलत बताया**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक कारणों से कई जाति प्रमाणपत्र रद्द किए जा रहे हैं। वहीं, राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप संभव नहीं है।

जरांगे ने मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर जालना जिले के अंतरवाली सराटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार कई कुनबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करके मराठा आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने में सुविधा दी और बाद में एक सुनियोजित रणनीति के तहत उन्हें रद्द किया जाना सुनिश्चित किया। उनका दावा था कि इसका निशाना मराठा समुदाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। जरांगे ने यह भी आरोप लगाया कि मराठा आंदोलन का विरोध करने वाले लोग मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच बना चुके हैं।

उन्होंने दावा किया कि राजस्व मंत्री बावनकुले ने अधिकारियों को प्रमाणपत्र रद्द करने के निर्देश दिए और इस प्रक्रिया से जुड़े आधिकारिक पत्राचार को मंजूरी दी। जरांगे लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि पात्र मराठाओं को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। कुनबी एक कृषक समुदाय है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समुदाय के खिलाफ कथित अन्यायपूर्ण कार्रवाई जारी रखती है तो मराठा समुदाय वर्ष 2029 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे ''बड़ा बदला'' लेगा और कई विधायकों की हार सुनिश्चित कर सकता है।

हालांकि, बावनकुले ने कहा कि सरकार या उसके किसी मंत्री को जाति सत्यापन समिति के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित करने वाली यह समिति अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जाति सत्यापन समिति स्वतंत्र रूप से काम करती है। न तो सरकार और न ही किसी मंत्री को समिति को बुलाने या उसे निर्देश देने का अधिकार है। समिति दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है।''

# तमिलनाडु कृषि बजट : किसानों को त्वरित सहायता देने के लिए एआई, मशीन लर्निंग का सहारा लेगी सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई/भाषा।** तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के कृषि बजट में कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित विशेष पहल 'उझावर एआई योजना' शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को वास्तविक समय में आंकड़ा आधारित सलाह उपलब्ध कराना है। विधानसभा में कृषि बजट पेश करते हुए तमिलनाडु के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने बताया कि इस योजना के लिए राज्य निधि से दो करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस पहल के तहत कृषि विस्तार सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। नई पहल के तहत किसानों को मोबाइल के माध्यम से बुआई से लेकर कटाई तक पूरी फसल अवधि के लिए तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी

के स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन, कीट एवं रोगों के प्रकोप की चेतावनी तथा क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसल संबंधी सुझाव शामिल होंगे।

ग्रामीण किसानों तक जानकारी की पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार 'वॉयस-फर्स्ट कृषि सेवाएं' शुरू करेगी। इसके माध्यम से किसान मोबाइल फोन पर आवाज के जरिये कृषि संबंधी सलाह, वास्तविक समय में बाजार की जानकारी और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। बजट दस्तावेजों में कृषि क्षेत्र के डिजिटल विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि तमिलनाडु की कृषि पारंपरिक निर्वाह खेती से आगे बढ़कर किसान समृद्धि पर केंद्रित एक प्रौद्योगिकी-संचालित, विज्ञान-आधारित मॉडल में बदल गई है।

एआई का यह एकीकरण 2021 में शुरू किए गए 'उझावर' मोबाइल ऐप जैसे पिछले डिजिटल प्रयासों की नींव पर आधारित है, जिसने राज्य के कृषि क्षेत्र में डेटा-आधारित प्रबंधन की शुरुआत की थी।

## द्रमुक ने कहा, टीवीके के कृषि बजट में ''कुछ नहीं''; कावेरी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई/भाषा।** तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने टीवीके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बृहस्पतिवार को कृषि बजट को 'पूरी तरह से खोखला' करार दिया और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर किसानों को 'धोखा देने' तथा प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने कावेरी जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने को लेकर भी सरकार की आलोचना की। द्रमुक की युवा इकाई के नेता की अगुवाई में विपक्षी दल के विधायक काली कमीज पहनकर तमिलनाडु विधानसभा पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी और मेकेदातु बांध संकट के मामले में कथित तौर पर कोई कदम न उठाए जाने के विरोध में विपक्षी विधायक काली कमीज पहनकर आए।

सरकार ने बृहस्पतिवार को अपना पहला कृषि बजट पेश किया। विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए उदयनिधि ने कृषि समुदाय के समक्ष मुख्य मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने और मौजूदा योजनाओं को 'केवल नया रूप देने' को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कृषि बजट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इसमें कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा, हम लगातार कावेरी और मेकेदातु मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। हमें यह दिखाना चाहिए कि तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। लेकिन हमेशा की तरह मुख्यमंत्री चुप हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।

उदयनिधि ने सरकार पर चुनावी वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों के सभी फसल ऋण माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार उसे पूरा करने में विफल रही है।

उदयनिधि ने बताया कि हालांकि शुरुआत में माफी की सीमा 50,000 रुपये तय की गई थी और बाद में किसानों की मांग पर इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया, किसान शुरू में किए गए वादे के मुताबिक पूरी माफी की मांग कर रहे हैं। अंतरराज्यीय जल विवाद का उल्लेख करते हुए उदयनिधि ने दावा किया कि कर्नाटक ने तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी जल छोड़ने से एकतरफा इनकार कर दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने इस मामले पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे तमिलनाडु के किसान मंझधार में फंस गए।

## अल नीनो से तमिलनाडु के 12 जिलों के अधिक प्रभावित होने की आशंका, कार्ययोजना तैयार : कृषि मंत्री

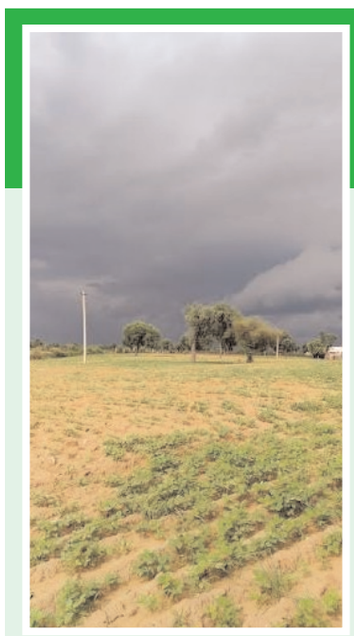

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई/भाषा।** तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर. विनोद ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सुपर अल नीनो की स्थिति के कारण राज्य के 12 जिलों के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार का पहला कृषि बजट पेश करते हुए विनोद ने कहा कि यह बजट विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कृषि योजनाओं को जारी रखने के साथ नई पहल भी शुरू की जाएंगी।

मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की कार्ययोजना लागू कर राज्य में सुपर अल नीनो से निपटने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मौसमीय घटना के कारण पूरे देश में, विशेषकर कुरुवई फसल मौसम (जून-जुलाई और अगस्त की शुरुआत) के दौरान गंभीर असर पड़ने की आशंका है।

विनोद ने कहा, पूर्वानुमान है कि तमिलनाडु के 12 जिले गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सभी जिलों के लिए तैयार जिला कृषि आकस्मिक योजना जिलाधिकारियों को भेज दी गई है और आकस्मिक उपायों को समग्र रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सभी योजनाओं और तकनीकी परामर्श सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए आठ नए एकीकृत कृषि विस्तार केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में 300 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम होगा। ये केंद्र तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर जिले के कटपडी और गुडियाथम, तिरुचिरापल्ली जिले के मुसिरी, विरुधुनगर जिले के नरिकुडी, थेनी जिले के बोडिनायकनूर, तूतीकोरिन जिले के कायाथार और कोयंबटूर जिले के थोंडामुथुर में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार की निधियों से 27.82 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए वर्ष 2026-27 में 43,500 किसानों को तिरपाल वितरित किए जाएंगे, ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोका जा सके और कृषि उपज को बारिश व धूप से बचाते हुए सुखाने तथा सुरक्षित भंडारण में मदद मिल सके। इसके लिए राज्य निधि से 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। लघु एवं सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2026-27 में राज्य स्तरीय फसल उत्पादकता प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

## एमडीएमके के दो विधायकों का इस्तीफा देने से इनकार, द्रमुक विधायक बने रहने की घोषणा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** एमडीएमके के दो विधायकों ने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि वे द्रमुक विधायक के रूप में बने रहेंगे।

कदयानलूर के विधायक टी एम राजेंद्रन और सिरकाझी के विधायक आर सेंथिल सेल्वन ने पांच अगस्त को संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हाल में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी, इसलिए वे आधिकारिक तौर पर द्रमुक के सदस्य हैं और विधानसभा में पार्टी के बैनर तले काम करेंगे। यह घोषणा हाल में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद की गई है, जिसमें वाइको के नेतृत्व वाली मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) ने द्रमुक से अपने संबंध तोड़ लिए थे।

विधायकों ने बताया कि एमडीएमके के महासचिव वाइको ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उन मतदाताओं के साथ धोखा होता जिन्होंने उन्हें चुना था। उन्होंने कहा, सिर्फ चार महीने में इस्तीफा देकर जनता के पास वापस जाना विरोधाभासी है और हम उनका सामना नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वाइको ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वादा किया था कि विधायक पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

उन्होंने स्वीकार किया कि उनके इनकार करने की वजह से उनके और एमडीएमके प्रमुख के बीच ''कड़वाहट'' पैदा हो गई। विधायकों ने एमडीएमके नेतृत्व की ओर से हाल में की गई आलोचना पर दुख जताया। उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा, ''हमने बिना किसी उम्मीद के 40 साल तक नेता वाइको का साथ दिया, लेकिन आखिर में हमें सिर्फ अपमानजनक बातें सुननी पड़ीं और हमें बुरा-भला कहा गया।'' विधायकों ने कहा कि उन्होंने शुरू में पार्टी नेतृत्व को यह जानकारी दी थी कि किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए वे छह महीने तक चुप रहेंगे। हालांकि, जब एमडीएमके के प्रधान सचिव ने आरोप लगाया कि ''वे बिक'' चुके हैं, तब उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा। दल बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए विधायकों ने कहा कि वे दोबारा चुनाव का टिकट या मंत्री पद जैसे लुभावने प्रस्तावों के झांसे में नहीं आए और न ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने का कोई फैसला किया।

## श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 'गैर-क्षेत्रीय तमिल समुदाय परिषद' के गठन का प्रस्ताव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कोलंबो/चेन्नई।** श्रीलंका में संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर भारतीय मूल के 'तमिल गैर-क्षेत्रीय तमिल समुदाय परिषद' (एनटीटीसी) के गठन की मांग करेंगे। तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस (टीपीए) के नेता मानो गणेशन ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। बुधवार को गणेशन ने श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल (आईओटी) समुदाय के नए बने समूह के अन्य नेताओं के साथ भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एनटीटीसी के लिए तय की गई भूमिका के बारे में बात की।

गणेशन ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक सुधार में न सिर्फ अधिकारों के बंटवारे को सुरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि संविधान में एनटीटीसी को शामिल करके भारतीय मूल के तमिल समुदाय की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को भी मान्यता दी जानी चाहिए।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मिसरी ने श्रीलंकाई नेतृत्व से अपील की कि वे जल्द से जल्द प्रांतीय परिषद चुनाव कराने के अपने वादे को पूरा करें और तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका के संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करें। गणेशन ने पीटीआई-भाषा' से कहा, ''यह चिंता वाजिब है कि नया संविधान 13वें संशोधन से मिली उपलब्धियों, खासकर प्रांतीय परिषदों के मामले में, उन्हें कमजोर कर सकता है। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए, भारत के पास ऐसी किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ आगाह करने का नैतिक अधिकार है, जो अधिकारों के बंटवारे को कमजोर करती हो।''

## बसवराज होर्रट्टी कर्नाटक विधानपरिषद के सभापति पद से देंगे इस्तीफा

**बेंगलूरु।** कर्नाटक विधानपरिषद के सभापति बसवराज होर्रट्टी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके पद नहीं छोड़ने की स्थिति में सत्तारूढ़ कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर चुकी है इसलिए वह अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे।

होर्रट्टी ने बुधवार देर रात मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी और उन्हें हटाए जाने के कदम पर चर्चा की थी। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानपरिषद सदस्य बी.के. हरिप्रसाद ने भी उनसे मुलाकात की। होर्रट्टी ने पत्रकारों से कहा, ऽऽसत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं। मुख्यमंत्री ने मुझसे फ़ोन पर दो बार बात की। कल उन्होंने मुझे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए बुलाया और बताया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें मुझसे इस्तीफा मांगने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया, तो कांग्रेस मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेगी।'' उन्होंने कहा कि वह ऽसम्मानपूर्वक' इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और उन्होंने 14 अगस्त को ऐसा करने का फ़ैसला किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पद छोड़ने से पहले वह सदन को घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा, ''देखते हैं सदन क्या कहता है।'' सभापति ने यह भी कहा कि वह इस घटनाक्रम से 'बहुत दुखी' हैं। होर्रट्टी ने कहा कि सदन में कांग्रेस के पास बहुमत है और वह अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए आसानी से उन्हें पद से हटा सकती है, ऐसे में उन्होंने इतने सालों में जो सम्मान कमाया है, उसे बचाए रखने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, ''जब यह राय हो कि मुझे अब इस पद पर नहीं रहना चाहिए, तो मैं इस पर बने नहीं रहना चाहता। मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने उन्हें बताया कि उन्हें हटाने का फ़ैसला पार्टी आलाकमान का है और वह व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करते हैं।

## इंडियन बैंक ने करीब 500 करोड़ रुपये के एमएसएमई ऋण की मंजूरी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई/नई दिल्ली।** सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने यहां आयोजित छोटे उद्यमों को कर्ज उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में करीब 500 करोड़ रुपये के एमएसएमई ऋण स्वीकृत किए। इंडियन बैंक ने बयान में कहा कि 120वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बिनोद कुमार ने बुधवार को 128 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। बैंक ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप एमएसएमई क्षेत्र के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बैंक देशभर में 120वें स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत वृहद ऋण मेले, कॉरपोरेट

सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल, डिजिटल बैंकिंग कार्यक्रम और ग्राहक संपर्क अभियान आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर लगभग 1,250 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्ताव जुटाए गए हैं, जो भविष्य में कारोबार बढ़ाने की मजबूत संभावनाओं को बताते हैं। कार्यक्रम के दौरान बैंक ने एकीकृत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) पोर्टल भी पेश किया। यह डिजिटल मंच एमएसएमई ग्राहकों को सहज और एकीकृत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है तथा प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण पर बैंक के ध्यान को मजबूत करेगा। कुमार ने कहा, ''इंडियन बैंक के 120 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम ग्राहक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग के माध्यम से समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2032 तक 35 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने के लक्ष्य के साथ हम वित्तीय समावेश को मजबूत करेंगे, एमएसएमई और उद्योगों को सशक्त बनाएंगे तथा निर्बाध डिजिटल बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराएंगे, जो भारत की विकास यात्रा को गति देंगे।'' बैंक का कुल कारोबार (कुल जमा और कुल ऋण) 30 जून, 2026 को 14 प्रतिशत बढ़कर 15,29,201 करोड़ रुपये रहा। इंडियन बैंक की स्थापना पांच मार्च, 1907 को 20 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी और बैंक ने 15 अगस्त, 1907 से अपना कारोबार शुरू किया था।

**उत्तर पश्चिम रेलवे**
खुली निविदा
ई-टेण्डर नोटिस सं. एस एंड टी प्रोजेक्ट-अजमेर-2026-27-01R दिनांक: 04/08/2026 उप मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/परियोजना/अजमेर भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से खुली निविदा सं. **एस एंड टी प्रोजेक्ट-अजमेर-2026-27-01R** जिसकी बंद होने की तिथि **27.08.2026** को ऑनलाईन ई-टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। कोई भी मैन्युअल टेण्डर संबंध में स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है उसको देखा नहीं जायेगा। **1. कार्य का नाम एवं लोकेशनः** Appointment of Project Supervision Services Agency (PSSA) for providing Project Supervision Services at various project Sites/ Sections in the jurisdiction of Dy.Chief Signal & Telecom Engineer/ Project Ajmer. **2. अनुमानित लागतः** ₹ 39195018.91, **3. टेण्डर जमा करने की अंतिम तारीखः** 27.08.2026, **4. वेबसाईट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशनः** www.ireps.gov.in or उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर/ परियोजना/अजमेर ऑफिस। **1144-PH/26**
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**उत्तर पश्चिम रेलवे**
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा सूचना संख्याः कैरिज-23-2026 दिनांकः 05.08.2026
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर कैरिज अजमेर द्वारा खुली ई-निविदा संख्याः कैरिज-23-2026 दिनांक 05.08.2026 को आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि कोई मैन्युअल टेंडर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **कार्य का नाम एवं स्थानः** "कैरेज वर्कशॉप, अजमेर में BG कोचों की सीटों/बर्थ को हटाना, उनकी मरम्मत करना और उन्हें लगाना।" **अनुमानित लागतः** रु. 2,07,35,555.34, **टेण्डर डॉक्युमेंट कॉस्टः** रु.00.00, **बयाना राशिः** रु. 414700.00, **ई-टेंडर फॉर्म जमा करने का समय व तारीखः** दिनांक 26.08.2026 समय 15.00 बजे तक, **वेबसाइट का विवरणः** www.ireps.gov.in, **पात्रता मानदंडः** लागू। **नोटः** टेण्डर डॉक्युमेंट कॉस्ट एवं बयाना राशी केवल किये IREPS की वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे सुविधा द्वारा ऑनलाइन जमा जाने है। **1150-PH/26**
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**उत्तर पश्चिम रेलवे**
पत्र सं.- WB-74-W-O/Works/NIT/X दिनांकः 03.08.2026
ई-निविदा आमन्त्रण सूचना
मंडल रेल प्रबन्धक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है- **ई-निविदा सूचना सं.:** 119 OF 2026-27, **कार्य का नाम व स्थानः** Raikabagh - Phalodi Jn, CTR(P)-92.000 Tkm (From Km 0.000 to Km92.000) by Contractors own PQRS/ SQRS portal under ADEN/Line-II Jurisdiction. **अनुमानित लागत रूपयेः** 378959461.26, **बयाने की राशि रूपयेः** 7579200.00, निविदा सूचना संख्या **119 OF 2026-27** निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 24.08.2026 को 15:00 बजे तक है। वेबसाईट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है- **www.ireps.gov.in** **1140-PH/26**
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**उत्तर पश्चिम रेलवे**
No. 580-W/Electronic/interlocking/ HSR/2026 Dated: 03.08.2026
ई-निविदा सूचना
संख्या 120 से 122 और 132 & 133-26-27
मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक **24.08.2026** को **15.00 बजे** तक खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्याः 120, कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर/भिवानी के अधीन बीकानेर डिवीजन में 11 ऐसे लेवल क्रॉसिंग पर जहाँ सड़क पर वाहनों का आवागमन अधिक है, सड़क की सतह को रबराइज्ड सतह से बेहतर बनाया जाने का कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** ₹ 12142132.08, **धरोहर राशिः** ₹ 242900.00; **निविदा संख्याः 121, कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर सिरसा के अधीन हिसार स्टेशन पर डिस्ट्रिब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था के सिलसिले में एस&टी बिल्डिंग, 3 संख्या ओसी हट और उससे जुड़े अन्य कार्यों की व्यवस्था। **अनुमानित लागत मूल्यः** ₹ 36084714.64, **धरोहर राशिः** ₹ 721700.00; **निविदा संख्याः 122, कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर/भिवानी के अधीन जोन नंबर 9(बी) भिवानी सब-डिविजन में स्टाफ क्वार्टर्स के लिए जोनल कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** ₹ 42319485.02, **धरोहर राशिः** ₹ 846400.00, **निविदा संख्याः 132, कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर/हनुमानगढ़-II के अधीन हनुमानगढ़ सरुपसर-श्रीगंगानगर-भटिंडा खंड (47.510 टीकेएम) में बैलास्ट क्लीनिंग मशीन द्वारा बैलास्ट नवीनीकरण कार्य के साथ-साथ सहायक कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** ₹ 20653468.16, **धरोहर राशिः** ₹ 413100.00; **निविदा संख्याः 133, कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर/हनुमानगढ़-II के अधीन हनुमानगढ़-सूरतपुरा खंड (48.880 टीकेएम) में बैलास्ट नवीनीकरण कार्य के साथ-साथ सहायक कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** ₹ 23300020.24, **धरोहर राशिः** ₹ 466000.00, **नोटः**- अन्य शर्तें रेलवे की वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। **1145-PH/26**
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग**
**भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन**
**(निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग)**
**इसरो टेलिमेट्रि ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक)**
प्लाट नं. 12 एवं 13, तीसरा मेन, द्वितीय फेज, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु-560058
फोन : 080-28094178, 4541, 4542 फैक्स : 080-28094180
**संक्षिप्त ई-निविदा सूचना**
1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, समुचित वर्ग के ठेकेदरों से निम्नलिखित कार्यों के लिए नग दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित आमंत्रित की जाती हैं।

| | |
|---|---|
| एनआईटी सं | इस्ट्रैक/सीएमजी/एमईसीएच/सीओएन/ईटीएन-62 / 2026-2027 दिनांक 06.08.2026 |
| कार्य का नाम | सीआईएसएफ बैरक, डीओएस इसरो हाउसिंग कॉलोनी, जालाहल्ली, बेंगलूरु में 01-नग यात्री लिफ्ट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य और 10 वर्षों के लिफ्ट के लिए सीएएमसी (दूसरी बोली) |
| निविदा का अनुमानित मूल्य | रु. 25.03 लाख भाग A के लिए<br>रु. 24.32 लाख भाग B के लिए |
| निविदा दस्तावेज विवरण | ई-निविदा |
| कार्य समापन अवधि, वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख के 15वें दिन से गिनी जाएगी। | तीन (03) महीने - भाग A के लिए<br>एक वर्ष की वारंटी अवधि के पश्चात 10 वर्ष - भाग B के लिए |
| निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि | 07.08.2026 को 16.00 बजे से 22.08.2026 को 16.00 बजे तक |
| बोली स्पष्टीकरण | 08.08.2026 को 11.00 बजे से 23.08.2026 को 16.00 बजे तक |
| बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख | 24.08.2026 को 16.00 बजे तक |
| निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय | 25.08.2026 को 16.00 बजे तक |
| निविदा खोलने की नियत तारीख और समय | 27.08.2026 को 11.00 से |
| अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी) | रु. 50,056.00 |

2. पात्रता मानदंड और दूसरी जानकारी के लिए, इच्छुक निविदाकार कृपया वेबसाइट www.isro.gov.in/Tenders.html पर टेंडर इनवाइटिंग का विस्तृत द्विभाषी (हिंदी - अंग्रेजी) नोटिस (NIT) देख सकते हैं और https://www.tenderwizard.com/ISRO पर टेंडर फ्री में देख सकते हैं।
ह/- समूह प्रमुख- सीएमजी

# रणथंभौर बाघ अभयारण्य क्षेत्र में दिखा सांभर, वन विभाग ने एएसआई को दिया नोटिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। रणथंभौर बाघ अभयारण्य क्षेत्र में कचरे के ढेर के पास एक सांभर दिखाई देने के बाद वन विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अभयारण्य के जिस क्षेत्र में कचरे की मौजूदगी पर एएसआई को यह नोटिस दिया गया उसमें साफ-सफाई की जिम्मेदारी एएसआई की है। घटना सामने आने के बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान की सफाई कराई। अधिकारियों ने बताया कि अब क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर दिया गया है और कचरे का उचित तरीके से निस्तारण किया गया है।

इस घटना के बाद रणथंभौर बाघ अभयारण्य के उप वन संरक्षक (डीसीएफ), एएसआई के अधिकारियों और त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रबंधन के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने, नियमित सफाई सुनिश्चित करने, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने, पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाने तथा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छता एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया।

# अशोक गहलोत ने डांगावास हत्याकांड में फैसले को बेहद चिंताजनक बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर डांगावास हत्याकांड में स्थानीय अदालत के फैसले को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद इंसाफ नहीं मिलना जांच और अभियोजन की गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। उल्लेखनीय है कि नागौर जिले के विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति) ने डांगावास हत्याकांड के सभी 40 आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया। साल 2015 में इस हत्याकांड में जमीन विवाद को लेकर पांच दलितों की हत्या कर दी गई थी। गहलोत ने एक बयान में कहा, नागौर के डांगावास हत्याकांड में 11 साल बाद आया फैसला बेहद चिंताजनक है।

2015 में जमीन विवाद में पांच दलितों समेत छह लोगों की निर्मम हत्या हुई थी और अब एससी-एसटी विशेष अदालत ने सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। पीड़ित परिवारों का सवाल जायज है, अगर 40 आरोपी बरी हो गए तो इन छह लोगों की हत्या आखिर किसने की?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच और सुनवाई के बावजूद इंसाफ नहीं मिलना जांच और अभियोजन की गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। उन्होंने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर भी निशाना साधा।

गहलोत ने कहा, भाजपा सरकार के शासन में 11 साल पहले ऐसी घटना होना और अब उन्हीं के शासन में प्रतिकूल फैसला आना दिखाता है कि भाजपा न्याय के पक्ष में नहीं है। दलित समाज के साथ हुए इस अन्याय में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलित समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए खड़ी रही है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़नी चाहिए, राज्य सरकार को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

# एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग के जोर पकड़ने के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को यहां राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

संगठन के कार्यकर्ताओं ने जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के द्वार पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया।

इस दौरान संगठन के कुछ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पुलिस अपने वाहनों में डालकर वहां से ले गई। एबीवीपी के विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संयोजक भारत भूषण यादव ने कहा कि राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं जिन्हें करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेगा।

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर चुकी है। संगठन से जुड़े तीन कार्यकर्ता पिछले हफ्ते यहां दो दिन तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे हालांकि कांग्रेस नेताओं के मनाने पर वे नीचे उतर आए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी बृहस्पतिवार को छात्रों ने छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

# मानसून सत्र से पहले दिल्ली में अमित शाह से मिले भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का 20 अगस्त से आगाज होगा। सत्र की तैयारियों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा अहम है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं, विधानसभा सत्र को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, संविधान और विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार, विधानसभा का सत्र नियमित अंतराल पर बुलाया जाना चाहिए। इन सत्रों के दौरान राजस्थान के विकास और जन-कल्याण से जुड़े मामलों पर चर्चा होती है, सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी जाती है और जनता के हित में बिल पेश करके उन्हें पारित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू करने का प्रस्ताव है। इस मानसून सत्र में राजस्थान की जनता के हित में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छे कामों को बढ़ाया जाएगा। उधर, मंत्री जोराराम कुमावत ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से सराहनीय काम कर रही है। सरकार समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है जिनसे सबसे वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत बनाने, महिलाओं को सशक्त करने, युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं कि गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचें। सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान' पहल भी शुरू की है, जो राज्य के विकास में योगदान दे रही है और साथ ही निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है।

# आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों की राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने गुरूवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं प्रलोभन-मुक्त वातावरण में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र मतदाता को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए आयोग के दिशा-निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात उसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्वाचन संबंधी शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण करने तथा प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने मतदान केन्द्रों पर पेयजल, बिजली, छाया, शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुरूप विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों से निर्वाचन कार्य में लगे सभी कार्मिकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा प्रत्येक गतिविधि की नियमित समीक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की कमी को समय रहते दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करे।

बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से जिला कलेक्टरों को निर्वाचन कार्यक्रम के विभिन्न चरणों, समयबद्ध कार्ययोजना तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। वर्मा ने मतदाता सूची को अद्यतन करने, मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं, कार्मिकों के प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता, कानून-व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना, शिकायतों के त्वरित निस्तारण, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाओं तथा निर्वाचन संबंधी मॉनिटरिंग तंत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से निर्धारित समय-सीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करने तथा आयोग के निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रस्तुतीकरण के दौरान जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों की ओर से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान करते हुए निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं एवं दायित्वों पर आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

# राजस्थान में बाल सुधार गृह के वार्डन की पीट-पीट कर हत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बाल सुधार गृह में वार्डन की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार बाल सुधार गृह में रह रहे तीन बाल अपचारियों (किशोरों) ने बुधवार रात वार्डन साहबराम को लकड़ी के फट्टे से पीटा। इस संबंध में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शहर की अम्बे विहार कॉलोनी के 63 वर्षीय साहब राम के रूप में हुई। वह पूर्व सैनिक थे। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा और हमले के कारण जानने के लिए उनकी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की प्रशासन से बातचीत चल रही है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों में से दो हत्या के व एक एनडीपीएस के मामले में बाल सुधार गृह में बंद है। उन्होंने बताया कि बाल सुधार गृह में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा चल रही थी तभी यह घटना घटी।

उन्होंने कहा कि साहब राम परिसर के अंदर खराब एयर कूलर की मरम्मत के लिए दूसरे सुरक्षा गार्ड से औजार लेने जा रहे थे तभी तीन किशोरों ने कथित तौर पर पीछे से लकड़ी के फट्टे से उन पर हमला कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, साहबराम के सिर में गंभीर चोटें आईं और वे मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूत खंगाल रही है।

# इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य को साकार करने के लिए बीमा एजेंसियां बढ़ाएं लक्ष्य : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा का सुदृढ़ कवच उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय बीमा गवर्निंग काउंसिल की द्वितीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी विजन 'इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047' के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए प्रदेश के अंतिम छोर तक बीमा सुरक्षा का दायरा विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि 'इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047' केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने सभी बीमा एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों का दायरा बढ़ाते हुए अधिकाधिक परिवारों को बीमा सुरक्षा से जोड़ें तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीमा एजेंसियां पंचायती राज विभाग के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करें, जिससे ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ा जा सके।

श्रीनिवास ने कहा कि आमजन के बीच बीमा के प्रति जागरूकता एवं विश्वास बढ़ाने के लिए सफल क्लेम सेटलमेंट के प्रेरक उदाहरणों और 'सफलता की कहानियों' का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

# राजस्थान में अनेक जगह भारी से अतिभारी बारिश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे के दौरान कई स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज बृहस्पतिवार को भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी है।

इसके अनुसार बृहस्पतिवार सुबह तक के 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वहीं पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी व कई जगह अतिभारी बारिश हुई। इस दौरान भरतपुर, डीग, अलवर व धौलपुर जिले में भारी से अतिभारी बारिश हुई। सबसे अधिक 170 मिलीमीटर (अतिभारी) बारिश रूदावल (भरतपुर) में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर का कहना है कि राजस्थान के कुछ भागों में 6-7 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व मानसून पुनः सक्रिय होने की पूरी संभावना है। छह अगस्त को भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

वहीं सात से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होगी।

इसी तरह 7-9 अगस्त को भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की चेतावनी है।

# 'हर घर तिरंगा' अभियान राष्ट्रप्रेम का सशक्त माध्यम : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान आज देश के सबसे सफल जनभागीदारी अभियानों में से एक बन चुका है। राष्ट्रप्रेम एवं देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है और इस वर्ष भी समन्वित एवं सुनियोजित प्रयासों से प्रदेश को इस अभियान में अग्रणी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जाएं। मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में एक बैठक लेकर सम्बंधित विभागों एवं जिला कलक्टरों को अभियान की निर्धारित कार्ययोजना का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रमुख स्मारकों, बांधों, सरकारी भवनों तथा एचआरआरएल रिफाइनरी सहित अन्य प्रमुख इमारतों को आकर्षक तिरंगा रोशनी से सजाने के निर्देश दिए। साथ ही अभियान के दौरान आयोजित सभी गतिविधियों के फोटो एवं अन्य विवरण

निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपलोड कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।मुख्य सचिव ने 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के आयोजन की तैयारियों के सम्बंध में कहा कि 14 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषकर युवा पीढ़ी को देश के विभाजन की त्रासदी से अवगत कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि 13 एवं 14 अगस्त को जिला एवं पंचायत स्तर पर विभाजन विषयक प्रदर्शनी तथा फिल्मों का प्रदर्शन आयोजित किया जाए। साथ ही, 14 अगस्त को जनप्रतिनिधियों, विभाजन प्रभावित परिवारों, स्वतंत्रता सेनानियों, स्वयं सहायता समूहों, कलाकारों, खिलाड़ियों तथा अन्य प्रबुद्ध नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला, पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शालीन सजावट, श्वेत पुष्पों से श्रद्धांजलि, दो मिनट का मौन तथा कैंडल मार्च आयोजित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेशभर में 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत जिला, नगरीय निकाय, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न जनभागीदारी आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 9 अगस्त को प्रातः 8 से 11 बजे तक प्रत्येक गांव एवं ढाणी में स्थानीय जनसमुदाय की सहभागिता से आयोजित तिरंगा प्रभात फेरी के साथ होगी।

# राजनाथ की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक, प्रादेशिक सेना पर चर्चा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक संसदीय समिति की बैठक में प्रादेशिक सेना पर चर्चा हुई और समिति के सदस्यों ने इसकी समग्र प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। सिंह ने कहा कि प्रादेशिक सेना प्रशिक्षित सैनिकों का एक रिजर्व' तैयार करके रक्षा बलों के लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मियों को तैयार रखती है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सकता है।

सिंह ने यहां रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रादेशिक सेना पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार, सचिव (रक्षा वित्त) विश्वजीत सहाय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के सदस्यों के समक्ष प्रादेशिक सेना के कामकाज, भूमिका और मुख्य उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सदस्यों ने इसे और मजबूत बनाने और इसकी कुल प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए।

अपने संबोधन में, सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में प्रादेशिक सेना के योगदान को महत्वपूर्ण'' बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां रक्षा बलों की भूमिका मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित होती है, वहीं प्रादेशिक सेना पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देती है। सिंह ने कहा, प्रादेशिक सेना 'नागरिक-सैनिक' अवधारणा का जीवंत उदाहरण है।

इसके सदस्य जहां एक ओर आम नागरिकों की तरह अपने कामकाज में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए वर्दी भी पहनते हैं।

उन्होंने कहा कि जब कर्मी अपना कार्यकाल पूरा करके एक आम नागरिक के तौर पर जीवन जीते हैं, तो वे समाज और सेना के बीच ''एक जीवंत सेतु'' की भूमिका निभाते हैं और लोगों, खासकर युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रादेशिक सेना एक प्रशिक्षित और मजबूत बल है, जिसमें लगभग 44,400 कर्मी और 59 अलग-अलग इकाइयां शामिल हैं। प्रादेशिक सेना का गठन 9 अक्टूबर 1949 को हुआ था। दशकों की अपनी यात्रा के दौरान इसने युद्ध के समय और मानवीय व पर्यावरण संरक्षण में देश की सेवा की है।

## लोकसभा में हंगामे के बीच कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के हंगामे के बीच 'कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026' को चर्चा के बिना पारित कर दिया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता'' उपलब्ध कराकर अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सभा ने के. राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन समेत कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया।

## युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार होगी प्रदेश की एकीकृत युवा नीति : मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**लखनऊ/भाषा।** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की एकीकृत युवा नीति को सूबे के युवाओं की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा नीति तैयार करने से पहले प्रदेश के 16 से 35 वर्ष के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाएगा और उसके बाद ही नीति को आकार दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की युवा नीति शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व विकास को एकीकृत करेगी। बयान के मुताबिक, आदित्यनाथ ने युवाओं के समग्र विकास की निगरानी के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र आयोग बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए 'सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार जोन' की स्थापना शीघ्र प्रारम्भ करने के भी निर्देश दिए।

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को और प्रभावी बनाने तथा हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तक इसके विस्तार पर विचार करने को भी कहा।

## बाढ़ प्रभावित अरुणाचल का दौरा करने के बाद नड्डा ने केंद्र की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**ईटानगर/भाषा।** केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के लिए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने केई पान्योर जिले के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालिया आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि नड्डा ने पोस्सा गांव और इससे सटी एनईईपीसीओ कॉलोनी का दौरा किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में राज्य के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है।

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और राज्य सरकार के साथ समन्वय कर प्रभावित परिवारों तक समय पर राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और वित्तीय मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नुकसान का विस्तृत आकलन पूरा होने के बाद क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नड्डा के साथ राज्य के शहरी विकास मंत्री बालो राजा, याचुली के विधायक टोको तातुंग, केई पान्योर जिले के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है; यह 28 जिलों में फैल गया है और इससे अनुमानित 1,55,858 लोग प्रभावित हुए हैं।

## स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 70 लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटे जाएंगे: शुभेंदु अधिकारी

**कोलकाता/भाषा।** पश्चिम बंगाल सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले 70 लाख राष्ट्रीय ध्वज वितरित करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य इस साल पहली बार केंद्र सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल हो रहा है। शुभेंदु ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत तिरंगे सभी जिलों, अनुमंडलों, नगरपालिकाओं और प्रखंडों में वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए इस अभियान में सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, युवा संगठनों और आम जनता की भागीदारी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों, होटल, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से भी इस अभियान में भाग लेने का आग्रह किया गया है। शुभेंदु ने बताया कि 10 अगस्त को कोलकाता में तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा।

## गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष का राज्यसभा से बहिर्गमन

**नई दिल्ली/भाषा।** नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया। तीन बार के स्थगन के बाद दो बज कर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक को चर्चा और लोकसभा को लौटाने के लिए पेश किया। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए कहा। इसी बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की और विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्ष की इसी मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही दिन में पहले ही तीन बार स्थगित की जा चुकी थी।

## एआई से बड़ी कंपनियों में नौकरियां घटेंगी, छोटे कारोबार बढ़ाएंगे रोजगार : नीलेकणि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्वचालन और कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल से भारत की बड़ी एवं सुव्यवस्थित कंपनियों में आने वाले वर्षों में नौकरियां घट सकती हैं, जबकि लाखों छोटे कारोबार भविष्य में रोजगार सृजन का प्रमुख आधार बनेंगे। 'एनसीएईआर इंडिया पॉलिसी फोरम-2026' को संबोधित करते हुए नीलेकणि ने कहा कि रोजगार सृजन को लेकर देश की सोच में बुनियादी बदलाव की जरूरत है।

नीलेकणि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के संचालन मंडल के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा, ''बड़ी कंपनियां, जो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से काम करती हैं, नौकरियों में कटौती के लिहाज से सबसे अधिक प्रभावित होंगी। इसका कारण यह है कि वहां हर काम कुछ तय कार्यों तक सीमित होता है, जिन्हें स्वचालन के जरिये आसानी से किया जा सकता है। इसलिए आने वाले वर्षों में बड़ी कंपनियां शुद्ध रूप से रोजगार घटाने वाली बन सकती हैं।'' इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य लाखों छोटे कारोबार क्षेत्रों में है, क्योंकि वे एआई से होने वाले बदलावों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हैं।

नीलेकणि ने कहा, ''लाखों छोटे कारोबार में एआई के जरिये व्यापक स्तर पर बदलाव करना कहीं अधिक जटिल है। इसलिए उन पर नौकरियों में कटौती का असर अपेक्षाकृत कम होगा और वे अधिक रोजगार सृजित करेंगे।'' उन्होंने कहा कि भविष्य में अर्थव्यवस्था इस सोच पर आगे बढ़ेगी कि कुछ कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार दें, इसके बजाय लाखों कंपनियां एक-एक व्यक्ति को रोजगार दें। नीलेकणि ने अनुमान जताया कि भारत में स्टार्टअप की संख्या 2035 तक बढ़कर 10 लाख हो सकती है, जबकि फिलहाल यह करीब 1.5 लाख है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर नियामकीय बोझ कम करने और कारोबार से जुड़े तंत्र को सरल बनाने की जरूरत है। छोटे उद्यमियों को अनावश्यक नियमों के बोझ से बचाने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे डिजिटल मंचों के माध्यम से उन्हें पूंजी और बाजार तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

## मामला केवल 'गुड टच' और 'बैड टच' तक सीमित था : बृजभूषण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**गोंडा/भाषा।** भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि पहलवानों से जुड़ा मामला केवल 'गुड टच' और 'बैड टच' तक सीमित था और इससे अधिक कुछ नहीं था।

गोंडा जिले के नंदिनी नगर महाविद्यालय में आयोजित 'सत्यमेव जयते' सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ''मैंने किसी की साड़ी खींचने का काम नहीं किया। मेडल पहनाते समय छुआ जाने (टच हो जाना) पर तूफान खड़ा कर दिया गया। मेरे खिलाफ लगाया आरोप राजनीति से प्रेरित है। यदि मैं इस प्रकरण में झुक जाता तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता।'' भाजपा के पूर्व सांसद ने दावा किया कि दुनिया में यौन उत्पीड़न के किसी मामले को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा, ''अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ और दुनिया के किसी भी बलात्कार के आरोपी के खिलाफ भी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ।'' सिंह ने कहा कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है और कई बार बिना वजह उनका नाम विवादों में घसीटा जाता है। उन्होंने कहा, ''संतों की कृपा मेरे ऊपर रहती है, इसलिए मैं हर संकट से बच जाता हूं।'' महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में गत तीन अगस्त को दिल्ली की अदालत से बरी होने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह के बृहस्पतिवार को पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

## उत्तर प्रदेश के पांच करोड़ घरों में फहराया जाएगा तिरंगा

**लखनऊ/भाषा।** राष्ट्र नायकों को सम्मान देने के साथ ही भावी पीढ़ी में देशभक्ति का संचार करने के लिए प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि हर घर तिरंगा' अभियान के तहत प्रदेश के पांच करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है। इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में तिरंगा संगीत समारोह' का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों-नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

सरकार ने कहा कि हर-घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत भव्य तिरंगा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण करने का निर्देश दिया।

# प्रधानमंत्री मोदी की 2025 में 23 देशों की यात्राओं पर 180 करोड़ रुपये से अधिक खर्च : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2025 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जापान समेत 23 देशों की यात्राओं पर 180 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। विदेश मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर देशवार और वर्षवार आंकड़े साझा किए गए। इसके अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर करीब 74.58 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें छह से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भी शामिल है।

आप के संजय सिंह और माकपा के वी. शिवदासन ने विदेश मंत्रालय से 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का देशवार विवरण और इन यात्राओं पर हुए खर्च का वर्षवार एवं यात्रा-वार ब्योरा मांगा था। विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने अपने जवाब में प्रधानमंत्री द्वारा 2021 से की गई विदेश यात्राओं और प्रत्येक यात्रा पर हुए कुल खर्च का वर्षवार तथा यात्रा-वार विवरण दिया। इसके अनुसार, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा (2011) पर 10,74,27,363 रुपये, रूस यात्रा (2013) पर 9,95,76,890 रुपये, फ्रांस यात्रा (2011) पर 8,33,49,463 रुपये और जर्मनी यात्रा (2013) पर 6,02,23,484 रुपये खर्च हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े महंगाई या मुद्रा विनिमय दर में बदलाव को समायोजित किए बिना वास्तविक खर्च को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री की विभिन्न देशों की यात्राओं पर करीब 187 करोड़ रुपये खर्च हुए। इनमें से फ्रांस यात्रा पर 25,59,82,902 रुपये, अमेरिका यात्रा पर 16,54,84,302 रुपये, सऊदी अरब यात्रा पर 15,54,03,792.47 रुपये, ब्राजील यात्रा पर 17,72,22,144 रुपये, चीन यात्रा पर 10,59,90,561 रुपये और ब्रिटेन यात्रा पर 9,91,55,061.39 रुपये खर्च हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2025 में मॉरीशस, थाईलैंड, श्रीलंका, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया, मालदीव, जापान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया की भी यात्रा की। सरकार ने जुलाई 2025 में राज्यसभा में एक अन्य लिखित जवाब में बताया था कि 2021 से 2024 तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल खर्च करीब 295 करोड़ रुपये रहा।

आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री की वर्ष 2024 में रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ब्राजील समेत 16 देशों की यात्राओं पर करीब 109 करोड़ रुपये, वर्ष 2023 में करीब 93 करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 55.82 करोड़ रुपये और वर्ष 2021 में करीब 36 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन की यात्रा की थी। इन यात्राओं पर क्रमश: 1,00,71,288 रुपये, 19,63,27,806 रुपये, 6,90,49,376 रुपये और 8,57,41,408 रुपये खर्च हुए थे।

## बाढ़ प्रभावित असम में जानवरों को बचाने में मदद के लिए वंतारा फाउंडेशन को धन्यवाद : मुख्यमंत्री हिमंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**गुवाहाटी/भाषा।** असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य में बाढ़ प्रभावित जानवरों को बचाने और अन्य राहत कार्यों में वन विभाग की मदद करने के लिए बृहस्पतिवार को वंतारा फांउडेशन का आभार जताया।

शर्मा ने कहा कि बाढ़ से मवेशियों और वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जानवरों को बचाने के काम पर अक्सर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा, असम में बाढ़ के नतीजों में से एक ऐसा पहलू जिस पर कम चर्चा हुई है, लेकिन जो बेहद दुखद है, वह है हमारे मवेशियों और वन्यजीवों पर पड़ी भारी मार। 10 लाख से अधिक मवेशी प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों जंगली जानवर बह गए हैं, और कई अन्य फंसे हुए हैं या लापता हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वन विभाग ने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन संकट का दायरा इतना बड़ा है कि और अधिक मदद की जरूरत है। शर्मा ने वंतारा फाउंडेशन का विशेष वन्यजीव बचाव टीम और एम्बुलेंस के बेड़े से राज्य के वन विभाग की मदद करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जानवरों को बचाने के काम पर अक्सर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। जो लोग इस नेक काम के लिए आगे आए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। श्री अनंत अंबानी के इस विचारशील और दयालु कदम के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं।'' असम में बाढ़ से कम से कम 95 लोगों की मौत हुई है और करीब 1.6 लाख प्रभावित हुए हैं।

## सुविचार

**मुस्कान एक ऐसी भाषा है, जिसे हर कोई समझता है। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, जीवन आसान लगेगा।**

## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

# बांग्लादेश में 'तूफान' की आहट

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की घोषणा कर इस पड़ोसी देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अगर वे अपने फैसले पर अडिग रहेंगी और बांग्लादेश लौटेंगी तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस घटना का असर भारत-बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पूरी कोशिश होगी कि शेख हसीना स्वदेश न लौटें। उनकी सरकार दबाव बनाने में जुट जाएगी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के बांग्लादेश लौटने से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को नई ऊर्जा मिलेगी। हो सकता है कि उस स्थिति में शेख हसीना को हवाईअड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए! उनके खिलाफ अदालतों में कई मामले लंबित हैं। कुछ नए मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को शांति के लिए खतरा बताकर हवाईअड्डे से ही जेल भेज सकती है। बांग्लादेशी समाज अपने तीव्र विरोध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। वहां ऐसी घटनाओं में भारी हिंसा का इतिहास रहा है। जब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यह खबर फैलेगी कि शेख हसीना आ रही हैं तो उनके समर्थक और विरोधी, दोनों में भयंकर टकराव हो सकता है। इन घटनाओं का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। अगर हालात बेकाबू हुए तो कई लोग भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सीमा पर तैनात हमारे सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शेख हसीना के समर्थक उनके भव्य स्वागत की तैयारियां करेंगे, भले ही पूर्व प्रधानमंत्री उन तक न पहुंचें। वे उनके सम्मान में जुलूस और जनसभाओं का आयोजन करेंगे। बांग्लादेश सरकार उन्हें रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाएगी।

जिन कथित आंदोलनकारियों ने अगस्त 2024 में उपद्रव मचाया था, वे दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि, इस बार उनकी भूमिका कुछ अलग हो सकती है। वे उस हवाईअड्डे पर धावा बोल सकते हैं, जहां शेख हसीना का विमान उतरेगा। यही नहीं, उन्हें जेल ले जाने की स्थिति में उस इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर, समर्थकों के घर भी चपेट में आ सकते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कट्टरपंथी तत्त्व उन पर हमला करने के लिए ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उनके आस-पास सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाने चाहिएं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ, महत्त्वपूर्ण दूतावासों, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को ईमेल भेजकर अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश सरकार पर दबाव पड़े और वह उन इलाकों की सुरक्षा की ओर ध्यान दे। भारतीय मीडिया और यूट्यूबरों को यह मुद्दा जोर-शोर से उठाना चाहिए। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय के ये शब्द असल हालात को बयान करते हैं- 'अगस्त 2024 से बांग्लादेश में राजनीतिक हत्याओं को वैध बना दिया गया है। आज बांग्लादेश एक विफल राष्ट्र है और वहां कानून व्यवस्था नहीं है। नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है।' शेख हसीना को हटाने के पीछे गहरी साजिश थी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के आम लोगों को हुआ है। जो देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसे ग्रहण लग गया है। कट्टरपंथियों की पौ-बारह हो गई है। यह स्थिति पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंताजनक है। भारत सरकार को अपना किरदार बहुत मजबूती से निभाना होगा।

## ट्वीटर टॉक

'सबका साथ-सबका विकास' का मंत्र आज समाज के हर वर्ग के उत्थान का कारण बन गया है। उत्थान की इस यात्रा का आधार 'घुमंतू विकास बोर्ड' है। म घुमंतू समाज द्वारा घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

**-योगी आदित्यनाथ**

आज एफएलओ कलेक्टिव 2026 एग्ज़िबिशन में शामिल हुआ, यह नेशनल हैंडलूम डे की सच्ची भावना के साथ आयोजित एक मौका था, जिसमें महिला सशक्तिकरण और हमारे कारीगरों के अमूल्य योगदान का जश्न मनाया गया।

**-दिया कुमारी**

डांगावास हत्याकांड मामले में 11 साल बाद आया फैसला बहुत चिंता की बात है। 2015 में, ज़मीन के झगड़े में पांच दलितों समेत छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और अब डउ-डढ स्पेशल कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है।

**-अशोक गहलोत**

## प्रेरक प्रसंग

# लोभ और आत्मसंयम

एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा 'गुरुदेव! चरक संहिता में अनेक स्थलों पर लोभ को रोकने की बात कही गई है और इसका संबंध रोगों से भी जोड़ा गया है, लेकिन मन में उत्पन्न होने वाली इस प्रवृत्ति को आखिर रोका कैसे जाए?' गुरुजी ने सीधे उत्तर देने के बजाय उससे पूछा, 'बताओ, हम अपनी आवश्यकता से अधिक जितना भी धन, वस्तुएं और साधन जीवन भर संचित करते हैं, क्या वे अंत में हमारे साथ जाते हैं?' शिष्य ने उत्तर दिया, 'नहीं गुरुदेव।' गुरुजी बोले, 'बस, इसी 'नहीं' को यदि मनुष्य समय रहते समझ ले तो लोभ पर नियंत्रण की शुरुआत हो सकती है। इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक अंग हैं और मनुष्य को कर्म तथा प्रगति के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताओं से बहुत आगे निकल जाती हैं तो वे लोभ का रूप धारण कर लेती हैं। लोभ की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं होती। इसलिए लोभ को रोकने का अर्थ इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि विवेक और आत्मसंयम द्वारा उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना है। लोभ को कम करने का एक प्रभावी उपाय दान और बांटने की प्रवृत्ति भी है। संग्रह मन को संकुचित करता है, जबकि दान मन का विस्तार करता है।'

## सामयिक

# संसदीय-गतिरोध : संवाद ही है समाधान

**ललित गर्ग**

**मोबाइल : 9811051133**

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। यही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श होता है, सरकार जवाबदेह बनती है, विपक्ष जनभावनाओं को स्वर देता है और कानूनों के माध्यम से देश के विकास की दिशा तय होती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद संवाद और सहमति का मंच बनने के बजाय टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक हठधर्मिता का अखाड़ा बनती जा रही है। मानसून सत्र में जिस प्रकार लगातार गतिरोध बना हुआ है, उससे केवल संसदीय कार्यवाही ही बाधित नहीं हो रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी आहत हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति बताती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक आग्रहों में इतने उलझ गए हैं कि राष्ट्रहित पीछे छूट गया है। विपक्ष की ओर से यह शर्त रखी जा रही है कि जब तक कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार सदन में बयान और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अडिग है। परिणाम यह है कि संसद का बहुमूल्य समय निरर्थक विवादों की भेंट चढ़ रहा है।

लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति को अराजकता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है, परंतु संसद को ठप कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है। जब विरोध संसद को चलने ही न दे, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्वों की उपेक्षा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है कि संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से उछाले जाते हैं, जिनके आधार पर पूरे सत्र को बाधित किया जा सके। परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं अथवा कई विधेयक लंबित रह जाते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान देश को होता है। संसद का प्रत्येक मिनट करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से संचालित होता है। यदि वह समय केवल शोर-शराबे और नारेबाजी में बीत जाए तो यह करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक विश्वास-दोनों का अपमान है।

लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय राजनीति की श्रेष्ठ परंपरा संवाद, सहमति और संवेदनशीलता की रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने दुराग्रह छोड़कर संवाद की मेज पर बैठें। संसद की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन किसे अधिक कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इस बात में है कि राष्ट्रहित के प्रश्नों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल आंदोलन और विरोध का नाम नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संभालने की होती है। यदि प्रत्येक मुद्दे पर संसद को बाधित करने की रणनीति अपनाई जाएगी तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नीति और दृष्टि का अभाव है। लोकतंत्र में जनता केवल विरोध नहीं, समाधान भी चाहती है। यदि विपक्ष स्वयं संवाद से दूरी बनाएगा तो संवाद से समाधान' का आदर्श केवल नारा बनकर रह जाएगा।

सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता। सरकार को भी विपक्ष की उचित मांगों को सुनना चाहिए और जहां संभव हो, सहमति का मार्ग निकालना चाहिए। संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। इसलिए सरकार को भी संवेदनशीलता, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। किंतु यदि संवाद का प्रत्येक प्रयास केवल राजनीतिक शर्तों और हठधर्मिता में उलझ जाए तो समाधान की संभावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक परिपक्वता की है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर मुद्दे को चुनावी लाभ-हानि के चश्मे से देखा जा रहा है। संसद में बहस कम और राजनीतिक संदेश अधिक दिए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद का उद्देश्य जनकल्याणकारी नीतियों पर विचार करना है, न कि चुनावी रणनीतियों का मंच बन जाना।

देश आज आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, रोजगार, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय संसद का प्रत्येक दिन अत्यंत मूल्यवान है। यदि यह समय केवल राजनीतिक टकराव में व्यतीत होगा तो विकास की गति अवश्य प्रभावित होगी। कानूनों में विलंब, नीतिगत निर्णयों की देरी और संसदीय अस्थिरता का सीधा प्रभाव आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस बात में नहीं कि संसद में कितना शोर हुआ, बल्कि इस बात में है कि वहां कितने सार्थक विचार सामने आए। स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष प्रतिद्वंद्वी अवश्य होते हैं, किंतु शत्रु नहीं। दोनों का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रहित होना चाहिए। यदि राजनीतिक दल इस मूल भावना को भूल जाएंगे तो लोकतंत्र केवल संख्या का खेल बनकर रह जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल आत्ममंथन करें। विपक्ष अपने विरोध को रचनात्मक बनाए, सरकार अपने संवाद को व्यापक बनाए और दोनों मिलकर संसद की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करें। लोकतंत्र का भविष्य टकराव में नहीं, संवाद में सुरक्षित है। संसद की गरिमा नारेबाजी से नहीं, विचार-विमर्श से बढ़ती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि संसद ही गतिरोध का प्रतीक बन जाएगी तो जनता का विश्वास कमजोर होगा, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। समय की पुकार है कि राजनीति चुनावों की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़े। पक्ष और विपक्ष दोनों यह स्मरण रखें कि वे किसी दल के नहीं, पहले भारत के प्रतिनिधि हैं। संसद की प्रत्येक घड़ी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उसे हठ, अहंकार और राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ाना भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। यदि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, संसद की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करनी है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो केवल एक ही मार्ग है-संवाद, सहमति और राष्ट्रहित। यही भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है और यही संसदीय मर्यादा का सर्वोच्च आदर्श।

## मंथन

# 'धुरंधर' पर अखिलेश की नाराजगी के सियासी मायने

**अजय कुमार**

**मोबाइल : 9335566111**

सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है, लेकिन जब परदे की कहानियां सीधे तौर पर चुनावी मैदान के समीकरणों और राजनीतिक दलों के इतिहास को प्रभावित करने लगें, तो सियासत गरमाना लाजिमी है। हाल ही में रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करने वाली फिल्म धुरंधर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने इस फिल्म को सीधे तौर पर एक सरकारी प्रोपेगेंडा करार देते हुए यह तक कह दिया है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी। आखिर क्या वजह है कि एक कमर्शियल फिल्म पर सूबे के इतने बड़े राजनेता को इतनी कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी और क्यों उन्होंने सरकार बनने पर जांच की बात कहकर राजनीतिक दांव चला है, इसे वर्तमान और अतीत के राजनीतिक घटनाक्रम के आईने में आसानी से समझा जा सकता है।

इस पूरे विवाद की जड़ में वह किस्सा है जिसका इस्तेमाल हालिया दौर के राजनीतिक नैरेटिव को गढ़ने के लिए किया जा रहा है। दरअसल, फिल्म धुरंधर और इसके सीक्वेंस में पूर्वांचल के एक चर्चित माफिया डॉन के किरदार और उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा आतंकी संगठनों के साथ संबंधों को परदे पर दिखाया गया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि उक्त माफिया राजनेता अतीत में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच चुका था। राजनीतिक विरोधियों ने इस सिनेमैटिक प्लॉट का इस्तेमाल तुरंत समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए हथियार के रूप में करना शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लगे उन पोस्टरों और विज्ञापनों ने आग में घी का काम किया, जिनमें सपा के पुराने शासनकाल की तुलना फिल्म के काल्पनिक और अराजक 'राज' से कर दी गई। जब किसी दल के पूरे राजनीतिक अतीत, उसकी कार्यप्रणाली और पुराने दौर के दागों को बड़े परदे के जरिए जनमानस के बीच इस तरह परोसा जाए कि सीधा संबंध किसी खास दल से जुड़े होने का आभास हो, तो दल के मुखिया के लिए उस पर प्रतिक्रिया देना राजनीतिक मजबूरी बन जाता है।

अखिलेश यादव का यह आक्रामक रुख महज एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भाजपा सरकार पर विपक्षियों की छवि धूमिल करने के लिए सरकारी तंत्र और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। अखिलेश ने यह सवाल उठाकर कि इस तरह के फिल्म निर्माण में भारी-भरकम पैसा कहां से आ रहा है और कौन लोग इसके पीछे हैं, एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उनका यह बयान इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी अब वैचारिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी आक्रामक तेवर अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। जब राजधानी में विपक्षी खेमे द्वारा लगातार ऐसे पोस्टर चस्पा किए जाएं जो पार्टी के पुराने शासनकाल को अपराध और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ के रूप में चित्रित करें, तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन हमलों को सिर्फ जुबानी जमाखर्च से न टालें, बल्कि भविष्य की सत्ता का विश्वास दिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखें और विरोधियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दें। सरकार बनने पर फिल्म निर्माण और इसके वित्तपोषण की जांच कराए जाने की बात कहकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के समर्थकों और कैडर को भी एक कड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों, कानून-व्यवस्था के मुद्दों और ब्राह्मणों के उत्पीड़न जैसे अन्य समकालीन मुद्दों के बीच, 'धुरंधर' जैसी फिल्मों के जरिए बन रहे नैरेटिव को काउंटर करना समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा बन गया है। अखिलेश भली-भांति समझते हैं कि यदि जनता के बीच इस प्रोपेगेंडा का माकूल जवाब समय रहते नहीं दिया गया, तो यह उनकी पार्टी की सेक्युलर और प्रगतिशील छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन होने पर केवल वर्तमान नीतियां ही नहीं, बल्कि इस प्रकार के राजनीतिक छद्म युद्धों और उनके वित्तीय स्रोतों की परतों को भी कानूनी दायरे में बेनकाब किया जाएगा।

## नजरिया

# गिरता भाषाई स्तर : संस्कृति, संस्कार और सामाजिक बोध का संकट

**डॉ स्नेहलता श्रीवास्तव**

**इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने अपनी भाषा की मर्यादा खोई, उन्होंने धीरे-धीरे अपने सांस्कृतिक संतुलन को भी खो दिया। सभ्यता का क्षरण अचानक नहीं होता; वह शब्दों से आरंभ होकर व्यवहार तक पहुँचता है और व्यवहार से मूल्य-व्यवस्था तक।**

मनुष्य का निर्माण केवल रक्त-मांस और अस्थियों से नहीं होता। उसका वास्तविक गठन उन सूक्ष्म संस्कारों, अनुभूतियों और सांस्कृतिक संकेतों से होता है जो पीढ़ियों के जीवन-अनुभव से छनकर उसकी चेतना में उतरते हैं। इसीलिए किसी समाज को समझने के लिए उसकी भाषा को पढ़ना अनिवार्य माना गया है। भाषा मनुष्य के संस्कारों, संवेदनाओं और सांस्कृतिक अनुशासन का दर्पण है। किसी सभ्यता की आत्मा उसकी भाषा में निवास करती है। शब्द केवल ध्वनियाँ नहीं होते; वे इतिहास की स्मृतियाँ, संस्कृति की परंपराएँ और समाज के नैतिक मूल्य अपने भीतर सँजोए रहते हैं। किसी व्यक्ति की भाषा उसके पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक परिवेश, अध्ययन, संवेदनशीलता और मानसिक परिपक्वता का परिचय देती है।वह वक्ता के आंतरिक संसार का प्रतिबिम्ब है।

भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्म और वाणी को सरस्वती का आसन माना गया। यह केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी; उसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक समझ थी। हमारे ऋषि जानते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बोलता है और जैसा बोलता है, धीरे-धीरे वैसा ही बनता जाता है। शब्द केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करते, वे विचारों का निर्माण भी करते हैं। इसीलिए सभ्यता का प्रारंभ वाणी के अनुशासन से होता है। जब कोई बालक बोलना सीखता है तो वह केवल शब्द नहीं सीखता, वह सम्मान करना, संबोधन करना, संबंधों का मूल्य समझना और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना भी सीखता है।

उसकी भाषा में घर का वातावरण बोलता है, माता-पिता की संवेदना बोलती है, पीढ़ियों का अनुभव बोलता है। भाषा संस्कृति का वह अदृश्य सेतु है जो व्यक्ति को समाज से और समाज को अपनी परंपरा से जोड़ता है। किन्तु आज इसी सेतु में दरारें पड़ती दिखाई देने लगी हैं। सार्वजनिक जीवन, राजनीति, मनोरंजन और विशेष रूप से सोशल मीडिया ने भाषा के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया है। संवाद की जगह प्रतिक्रियाएँ ले रही हैं, विचार-विमर्श की जगह आरोप-प्रत्यारोप और तर्क की जगह उत्तेजना। शब्दों की गरिमा से अधिक उनके प्रहार की क्षमता को महत्त्व मिलने लगा है। कटुता को स्पष्टवादिता, अभद्रता को निर्भीकता और अपमान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर्याय माना जाने लगा है।

इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने अपनी भाषा की मर्यादा खोई, उन्होंने धीरे-धीरे अपने सांस्कृतिक संतुलन को भी खो दिया। सभ्यता का क्षरण अचानक नहीं होता; वह शब्दों से आरंभ होकर व्यवहार तक पहुँचता है और व्यवहार से मूल्य-व्यवस्था तक। इसलिए भाषा की चिंता वस्तुतः संस्कृति की चिंता है, वाणी की रक्षा वास्तव में मनुष्यता की रक्षा है। आज आवश्यकता केवल शुद्ध भाषा की नहीं, शुद्ध चेतना की है। परिवारों में संवाद की संस्कृति लौटे, साहित्य शब्दों की गरिमा का पुनः स्मरण कराए, शिक्षा व्यक्तित्व और वाणी के संबंध को समझाए तथा समाज यह स्वीकार करे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभद्रता समानार्थी नहीं हैं। शब्दों की मर्यादा कोई बंधन नहीं, बल्कि सभ्यता का सौंदर्य है। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों, वैभव या उपलब्धियों से पहले उसकी वाणी से होती है। भाषा वक्ता के मानसिक स्तर का प्रतिबिम्ब होती है। शब्दों की शालीनता में ही संस्कृति का माधुर्य, समाज की संवेदना और मनुष्य की गरिमा सुरक्षित रहती है। इसलिए भाषा का प्रश्न केवल भाषाविदों का प्रश्न नहीं, सम्पूर्ण सभ्यता के भविष्य का प्रश्न है।इस दिशा में सभी को समय रहते चिंतन करना चाहिए।

**महत्त्वपूर्ण**

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

## रानी-प्रिया कपूर विवाद

# उच्चतम न्यायालय को आपसी सहमति से समझौते की उम्मीद

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक न्यास को लेकर जारी विवाद में बृहस्पतिवार को कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया काफी ''संतोषजनक'' ढंग से बढ़ रही है और उसे ''उम्मीद'' है कि यह विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थ की ओर से दाखिल शुरुआती मध्यस्थता रिपोर्ट पर गौर किया। पीठ ने कहा, ''हमने देखा है कि अबतक मध्यस्थता की प्रक्रिया छह सत्रों में हुई है। मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। हमें यह जानकर खुशी है कि मध्यस्थता काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। हमें इस बात से भी खुशी है कि सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं।'' शीर्ष अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मध्यस्थ ने दो नवंबर तक मध्यस्थता के लिए समय देने का अनुरोध किया है।

पीठ ने कहा, ''...(संबंधित) पक्षों को खुले मन और दिल से मध्यस्थ के पास जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी लंबे कानूनी विवाद में न फंसें। मध्यस्थता को बढ़ने दें, हम एक और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।'' न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान ''आरके फैमिली ट्रस्ट'' से किया जाए और इस संबंध में आगे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पीठ ने संबंधित पक्षों से कहा, ''अगर मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो हम आप सभी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, लेकिन ऐसा दिन न आने दें।'' इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद में मध्यस्थ के तौर पर काम करने के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को संजय कपूर की मां की ओर से दायर उस मुकदमे पर प्रिया कपूर और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें फ़ैमिली ट्रस्ट को ''अमान्य'' घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों से 'फ़ैमिली ट्रस्ट' से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता तलाशने को भी कहा था। इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान गिर जाने के बाद 12 जून, 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था।

# लद्दाख भारत की पहली अत्यधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी शुरू करेगा

लेह/जम्मू/भाषा। भारत की पहली अत्यधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी लद्दाख में शुरू होने जा रही है। उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने स्थानीय समुदायों को वन्यजीव संरक्षण और आर्थिक विकास में समान भागीदार बनाने तथा सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिम तेंदुआ और पक्षी अवलोकन मार्गों पर गाइड के साथ जीप सफारी को मंजूरी दे दी है।

अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय नवगठित हिम तेंदुआ और 'उच्च पर्वतीय प्रकृति' (एसएचएएन) संरक्षण सोसाइटी की पहली शासी निकाय की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल ने की थी।

उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत वन विभाग को काजीरंगा और रणथंभौर जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में संचालित सफारी की तर्ज पर गाइड के साथ जीप सफारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ऐसे विशेष वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनका पिछला हिस्सा खुला होगा, जिनका संचालन प्रशिक्षित स्थानीय चालक और गाइड करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य निर्धारित मार्गों से हटकर वाहन चलाने पर रोक लगाना और वन्यजीवों को होने वाले व्यवधान को कम करना है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य विनियमित और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना भी है।

# तब्बू को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का निर्देश देगा कोर्ट

**नई दिल्ली/एजेन्सी**

बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम रुख अपनाया है। अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह अभिनेत्री के नाम से जुड़े आपत्तिजनक और अश्लील ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगी। अदालत ने माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी सार्वजनिक व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल गंभीर विषय है और ऐसे मामलों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने की जरूरत भी हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेगा। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ के समक्ष तब्बू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अभिनेत्री ने अदालत से अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके नाम, तस्वीर, पहचान और व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी पहचान का इस्तेमाल कर एआई से तैयार कंटेंट और डिजिटल इम्पर्सोनेशन के जरिए भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान तब्बू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने अदालत को बताया, ''कोर्ट के पिछले निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को प्रतिवादी के रूप में सही तरीके से शामिल करने के लिए पक्षकारों की सूची में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। इंटरनेट पर कुछ लोग अभिनेत्री के नाम को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के साथ जोड़कर सर्च कर रहे हैं। संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे सर्च से लाभ भी कमा रहे हैं, जिससे न केवल अभिनेत्री की छवि प्रभावित हो रही है बल्कि उनकी पहचान का व्यावसायिक फायदा भी उठाया जा रहा है।''इन दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, ''जिन लिंक की पहचान की गई है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। ऐसे आपत्तिजनक लिंक को हटाने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।''

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा, जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी की जाएगी। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों की पर्सनैलिटी राइट्स के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामलों की

संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य में आने वाले मामलों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे अदालतों और संबंधित पक्षों को ऐसे मामलों के निपटारे में एक समान प्रक्रिया अपनाने में मदद मिलेगी।

हाल के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इस तरह के मामलों में भी तेजी आई है। एआई के जरिए किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज या पहचान का इस्तेमाल कर नकली सामग्री तैयार करना अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यही वजह है कि कई सितारे अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं।

# अमिताभ बच्चन ने बताया भोजपुरी फिल्म का किस्सा, बोले-अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ की थीं दो फिल्में

**मुंबई/एजेन्सी**

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का आगाज कर दिया है। एक एपिसोड में कंटेस्टेंट के साथ मजेदार बातचीत में अभिनेता ने अपने भोजपुरी सिनेमा में काम करने के अनुभव को साझा किया। शो के होस्ट चैनल ने एपिसोड अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कंटेस्टेंट ने कहा कि बिहार के लोग अमिताभ बच्चन को बहुत मानते और पसंद करते हैं। साथ ही, कंटेस्टेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो और ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम करें। कंटेस्टेंट की बात का मान रखते हुए अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, सर, हमारे मेकअप मैन का नाम दीपक है, मैंने जब भोजपुरी फिल्में की थी, तो ये हमारे साथ थे। आपने अब तक नहीं देखी क्या? इसके बाद कंटेस्टेंट ने कहा, हां, आपकी फिल्म 'गंगा' है लेकिन आप ओटीटी पर भी आइए और भोजपुरी में भी काम कीजिए।ये सुनकर अमिताभ बच्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गए और अपने अंदाज में बोले, अरे, वो भोजपुरी वाली ही फिल्म थी। कंटेस्टेंट ने आगे बातचीत में बताया कि उनका बेटा मेगास्टार अमिताभ बच्चन को 'केबीसी अंकल' के नाम से जानता है।

# 'एमटीवी हसल 5' की इनामी राशि बढ़कर हुई 1 करोड़ रुपए हुई

**मुंबई/एजेन्सी**

म्यूजिक रियलिटी शो 'एमटीवी हसल' पांचवें सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। इस बार शो को पहले से ज्यादा बड़ा बनाने की तैयारी है। इस बार विजेता राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शो के जज बादशाह का कहना है कि यह सिर्फ इनाम की रकम में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि भारतीय हिप-हॉप कल्चर की बढ़ती ताकत और कलाकारों पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है। 'हसल' हमेशा से ऐसे कलाकारों को खोजने का मंच रहा है, जिनके पास कहने के लिए अलग कहानी होती है और जो अपनी कला के जरिए पहचान बनाना चाहते हैं। बादशाह ने नए सीजन के बारे में बात करते हुए कहा, ''हसल हमेशा से ऐसे कलाकारों को सामने लाने के लिए रहा है, जिनके पास कुछ वास्तविक कहने के लिए है। हर सीजन में हमने देश के अलग-अलग हिस्सों से शानदार टैलेंट देखा है, जिन्होंने भारतीय हिप-हॉप में अपनी एक जगह बनाई है।''

उन्होंने आगे कहा, इस बार विजेता को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह राशि बताती है कि हिप-हॉप संस्कृति कितनी आगे बढ़ चुकी है। यह इनाम उन कलाकारों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जो भारतीय हिप-हॉप के भविष्य को आकार दे रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इस सीजन की थीम 'अपना होमग्राउंड' है, जो हर कलाकार की शुरुआत, उसकी जगह और उसकी कहानी को सम्मान देती है।

'एमटीवी हसल 5' की थीम 'अपना होमग्राउंड' के जरिए उन जगहों और अनुभवों को दिखाने की कोशिश की जाएगी, जहां से कलाकारों की यात्रा शुरू होती है। शो में देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रतियोगी निजी कहानियों, संस्कृति और संगीत के अंदाज को मंच पर पेश करेंगे। शो का उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ रहे हिप-हॉप कल्चर की विविधता को सामने लाना है।

# मल्लिका शेरावत के साथ नजर आए तेज प्रताप यादव

**पटना/एजेन्सी**

बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों मनोरंजन जगत में अपनी मौजूदगी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर उन्होंने फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस वीडियो में तेज प्रताप बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों को एक साथ देखकर इंटरनेट पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल, तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स टाइमलाइन पर यह वीडियो साझा किया है। वीडियो में वह अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत होती नजर आ रही है। वीडियो में तेज प्रताप अपने मोबाइल फोन में मल्लिका शेरावत को कुछ दिखा रहे हैं, वहीं मल्लिका भी पूरे ध्यान से मोबाइल की ओर देखती हैं और बीच-बीच में तेज प्रताप से बातचीत करती दिखाई देती हैं। इस वीडियो को और खास बनाने के लिए इसके बैकग्राउंड में फिल्म 'धुरंधर' का रोमांटिक गाना 'गहरा हुआ' लगाया गया है। गाने के साथ तैयार किया गया यह छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

तेज प्रताप यादव ने वीडियो के साथ यह जानकारी साझा नहीं की है कि उनकी और मल्लिका शेरावत की यह मुलाकात कब और किस मौके पर हुई, लेकिन उन्होंने कैप्शन के जरिए कुछ दिलचस्प सा संकेत जरूर दिया है।उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ''जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है''वीडियो के सामने आने के बाद कई लोग इसे किसी शूटिंग या कार्यक्रम के दौरान हुई मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे 'भोजपुरी बवाल' से जोड़कर भी देख रहे हैं।दरअसल, तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में हिस्सा लिया है। शो के एक एपिसोड में उन्होंने भोजपुरी फिल्म उद्योग पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में पहले अच्छी और पारिवारिक कहानियां देखने को मिलती थीं, लेकिन अब उनमें अश्लीलता बढ़ गई है। उन्होंने इच्छा जताई थी कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वह भोजपुरी सिनेमा को उसकी पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे। 'भोजपुरी बवाल' में तेज प्रताप यादव के साथ भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े सितारे भी नजर आ रहे हैं। इनमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं।

# राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं, कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने संपत्तियों पर चिपकाया नोटिस

**मुंबई/एजेन्सी**

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे अभिनेता के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। बैंक ने शाहजहांपुर स्थित राजपाल यादव की दो संपत्तियों को नीलामी के लिए चिह्नित करते हुए वहां नोटिस चस्पा कर दिया है। बैंक का कहना है कि अभिनेता पर करोड़ों रुपए का कर्ज बकाया है, जिसकी वसूली के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा ने शाहजहांपुर में स्थित राजपाल यादव की संपत्तियों पर नीलामी संबंधी नोटिस लगाया है। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक, अभिनेता पर 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपए का ऋण बकाया है। बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए उनकी

गिरवी रखी गई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक द्वारा जिन संपत्तियों की नीलामी की जा रही है, उनमें शाहजहांपुर शहर में स्थित एक संपत्ति और गांव में स्थित खेत व मकान शामिल हैं। इन दोनों संपत्तियों का आरक्षित मूल्य बैंक ने 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए तय किया है। बैंक की ओर से जारी प्रक्रिया के अनुसार, इन संपत्तियों की ई-नीलामी 9 सितंबर 2026 को कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने यह ऋण अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए लिया था। फिल्म के निर्माण के लिए बैंक से आर्थिक मदद ली गई थी लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। इसके बाद ऋण की किस्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाया और धीरे-धीरे ब्याज बढ़ता गया। अब यह रकम बढ़कर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है।

ऋण लेते समय राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को भी गारंटर के रूप में गिरवी रखा था। बैंक अब इसी आधार पर संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के अलावा मुंबई स्थित उनकी कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर भी बैंक की वसूली प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी।

## इवेंट

मुंबई में प्लेग्राउंड सीजन 5 के प्रमोशनल इवेंट के दौरान तस्वीरें खिंचवाते टीवी कलाकार तेजस्वी प्रकाश, एलविश यादव और आरुष भोला।

# आधा समय काम और खाने की चर्चा में बीतता है : रकुल प्रीत सिंह

**मुंबई/एजेन्सी**

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और निर्माता-अभिनेता जैकी भगनानी की जोड़ी ने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा है, लेकिन समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी खूबसूरत झलकियां भी साझा करते रहते हैं। हाल ही में रकुल ने जैकी के साथ अपने काम और निजी रिश्ते को लेकर एक खास बात साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि पति के साथ काम करना उनके लिए कितना खास और मजेदार अनुभव है। रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर जैकी भगनानी के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं।

इन तस्वीरों में दोनों के बीच की खास बॉन्डिंग नजर आ रही है। पोस्ट में रकुल ने फैंस द्वारा पूछे जाने वाले उस सवाल का जवाब

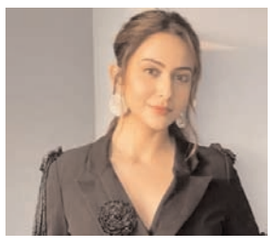

दिया कि पति के साथ काम करना कैसा होता है। रकुल ने अपने कैप्शन में लिखा, ''जब लोग मुझसे पूछते हैं कि साथ काम करने का अनुभव कैसा है, तो इसका जवाब बहुत आसान है। हम दोनों का आधा समय काम को लेकर बातचीत करने में और बाकी समय हंसी-मजाक करने और खाने की चर्चा करने में बीतता है।

मुझे यह अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी सोच और तालमेल एक जैसी है। जब दो लोग किसी काम को लेकर एक जैसी एनर्जी और उत्साह रखते हैं तो साथ मिलकर कुछ नया बनाना और भी खास हो जाता है।''

अभिनेत्री ने आगे लिखा, ''साथ मिलकर जिंदगी बनाना अपने आप में एक अलग अनुभव है, लेकिन जब आप दोनों मिलकर ऐसी चीज बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे लेकर दोनों उत्साहित हों, तो वह सफर और भी खास बन जाता है।''

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने साल 2021 में अपने रिश्ते का खुलासा किया था। इसके बाद दोनों ने 2024 में गोवा में शादी की थी। उनकी शादी में परिवार के करीबी लोग और खास दोस्त शामिल हुए थे। शादी के बाद भी दोनों अपने-अपने काम में सक्रिय हैं और अक्सर एक-दूसरे को सहयोग करते नजर आते हैं।

## स्क्रीनिंग

मुंबई में फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी की स्क्रीनिंग के दौरान पति राज कुंद्रा और सास ऊषा रानी कुंद्रा के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी।

# मॉडलिंग क्या होती है, ये भी नहीं जानती थीं : तनुश्री चक्रवर्ती

मुंबई/एजेन्सी

फिल्मों की दुनिया में कई सितारों का सफर किसी प्लानिंग के तहत शुरू नहीं होता। कुछ लोग अचानक मिले मौके को अपनी मेहनत से बड़ी पहचान में बदल देते हैं। बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज वह अपनी खूबसूरती, अभिनय और अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था, तब उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक मामूली शुरुआत से तनुश्री ने धीरे-धीरे विज्ञापनों, फिल्मों और फिर राजनीति तक का सफर तय किया। तनुश्री चक्रवर्ती का जन्म 6 अगस्त 1984 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से जुड़े बसंती देवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या होती है।तनुश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, तब उन्हें नहीं पता था कि मॉडलिंग में काम कैसे होता है और इस क्षेत्र की असली दुनिया कैसी है। धीरे-धीरे उन्होंने इस काम को समझा और कई विज्ञापनों में नजर आने लगीं। उनका एक बांग्लादेशी मसाला ब्रांड का विज्ञापन काफी लोकप्रिय हुआ, जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई। यही छोटा सा कदम आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत बना।मॉडलिंग के बाद तनुश्री ने बंगाली फिल्मों में कदम रखा। साल 2010 में फिल्म 'बोंधु एसो तुमी' से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की।

इसके बाद साल 2011 में आई फिल्म 'उरो चिट्ठी' ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बंगाली सिनेमा की कई चर्चित फिल्मों में काम किया। साल 2012 में आई 'बेडरूम' उनके करियर की अहम फिल्मों में से एक रही। इसके बाद उन्होंने 'ओबिशोप्टो नाइटी', 'विंडो कनेक्शन्स', 'बुनो हांश' और 'खाद' जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। उनकी एक्टिंग को दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने काफी पसंद किया।

उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाएं ही नहीं कीं, बल्कि अलग तरह के किरदारों के जरिए अपनी अभिनय क्षमता भी दिखाई। तनुश्री चक्रवर्ती ने फिल्मों के साथ-साथ टीवी की दुनिया में भी काम किया। वह जी बांग्ला के लोकप्रिय शो 'दीदी नंबर. 1' में नजर आईं और बाद में कई टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनीं। उन्होंने ब्यूटी और लाइफस्टाइल शो 'संपूर्ण' की होस्टिंग भी की। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता में अपने रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत भी की। साल 2021 में तनुश्री ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन की और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में श्यामपुर सीट से चुनाव लड़ा।

# जीवन का लक्ष्य केवल जीना नहीं, जागना है : आचार्य कुलबोधिसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित आचार्य श्री कुलबोधिसूरिश्वरजी ने गुरुवार को 'शांत सुधा रस' ग्रंथ के आधार पर प्रवचन देते हुए कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल जीना या जीतना नहीं, बल्कि जागृत होना है। उन्होंने एक प्रेरक दृष्टांत सुनाते हुए बताया कि जैसे एक धावक चोर का पीछा करते-करते अपना वास्तविक उद्देश्य ही भूल गया, उसे यह भी याद नहीं रहा कि चोर उसका बटुआ लेकर भाग गया, और भागते-भागते वह चोर से आगे निकल गया। उसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक दौड़-भाग की आपाधापी में अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूल बैठा है।

आचार्यश्री ने कहा कि शांत सुधा रस ग्रंथ जीवन के वास्तविक लक्ष्य का बोध कराता है। उन्होंने जीवन के तीन लक्ष्य जीना, जीतना और जागना के संदर्भ में कहा कि जीना तो पशु भी जानते हैं, जीतना भी अनेक लोग सीख लेते हैं, किंतु मनुष्य जन्म की सार्थकता आत्मजागृति में है। उन्होंने कहा, चिता जलने से पहले चेतना जगा लो, अस्थियां बिखरने से पहले आस्था को जगा लो। हमने कई ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया लेकिन अभी भी मोह की नींद में सोए हुए हैं।

महोपाध्याय विनयविजयजी महाराज ने इस ग्रंथ में वर्णित बारह भावनाओं के माध्यम से बार-बार आत्मा को जगाने का संदेश दिया है। आप ही निर्धारित करो कि आपका लक्ष्य क्या है जीना, जीतना या जागना?

# 'बम बोल' के जयकारों के साथ कवाड़ यात्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई के मद्रास कांवड़ संघ द्वारा आयोजित रजत जयंती वर्ष (2002-2026) की पावन कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सेवा एवं शिवभक्ति के साथ निरंतर देवघर मार्ग पर आगे बढ़ रही है। संघ के 85 श्रद्धालु शिवभक्तों ने अब तक अपनी चार दिवसीय पदयात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। यात्रा के प्रथम चार पड़ाव क्रमशः असरगंज, मनिया मोड़, जिलेबिया मोड़ एवं अबरखा में सम्पन्न हुए, जहाँ देशभर से आने वाले हजारों कांवड़ यात्रियों के लिए मद्रास कांवड़ संघ द्वारा निःस्वार्थ भाव से सेवा कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। यात्रा में महिला श्रद्धालुओं एवं वरिष्ठ कांवड़ियों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा का शेष भाग भी इसी उत्साह एवं सेवा-भाव के साथ सम्पन्न किया जाएगा। यात्रा में लक्ष्मणगढ़ के भजन गायक पवन शर्मा 'निर्मल' अपनी संपूर्ण भजन मंडली के साथ प्रतिदिन भगवान शिव के भजनों की ऐसी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं।

नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रभुदयाल जोशी का अभिनंदन करते हुए समाज के सदस्यगण एवं चित्र के इंसर्ट में अध्यक्ष।

# सिखवाल ब्राह्मण समाज बेंगलूरु के अध्यक्ष बने प्रभुदयाल जोशी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के अल्सूर स्थित उदासीन मठ में सिखवाल समाज के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति श्रृंगी ऋषि जयंती महोत्सव धूम धाम से मनाया गया। समाज के वरिष्ठ एवं पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन जोशी ने बताया कि महोत्सव के पश्चात् वार्षिक मीटिंग बुलाई गई जिसमें समाज के वरिष्ठ जनो की उपस्थिति में सर्व सम्मति से अध्यक्ष का दायित्व पण्डित प्रभु दयाल जोशी को दिया गया। उनके साथ उपाध्यक्ष का दायित्व सुनील तिवारी को तथा कोषाध्यक्ष पद का कार्यभार प्रकाश चन्द्र व्यास को सौंपा गया। नव मनोनीत अध्यक्ष प्रभुदयाल जोशी एक सामान्य परिवार से मूलतः कबराडीया भीलवाड़ा के राजस्थान के निवासी हैं तथा बेंगलूरु में कृष्ण ज्योतिष कार्यालय के संचालक हैं। वे विनम्र और सेवाभावी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जोशी ने उपस्थितजन को विश्वास दिलाया कि वे अपने दायित्व को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही समाज की एकता, सेवा व प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के समापन पर आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस आयोजन में श्याम लाल तिवारी, रामगोपाल तिवारी, अशोक पांडिया, गजानन्द शर्मा सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

# श्रद्धा, सूत्रज्ञान और गुरु-परंपरा से ही तत्त्वज्ञान का साक्षात्कार संभव : मुनिश्री तीर्थचैतन्य

चेन्नई। यहां किलपॉक जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित मुनिश्री तीर्थचैतन्य विजयजी ने गुरुवार प्रातः प्रवचन में कहा कि साढ़े बारह वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरे भव में समस्त जीवों के कल्याण की भावना से की गई विशुद्ध साधना के फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का निकाचन किया था। केवलज्ञान के अगले दिन गौतम स्वामी सहित ग्यारह गणधरों को प्रथम देशना प्रदान की गई, जिसे गणधर भगवंतों ने अपनी विलक्षण बीज-बुद्धि' से द्वादशांगी आगम के रूप में संकलित कर मानवता के लिए सुरक्षित रखा।

मुनिश्री ने कहा कि भगवान महावीर ने लगभग तीस वर्षों तक धर्मदेशना देकर जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग दिखाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक जीव आध्यात्मिक पीड़ा से ग्रस्त है और उसका उपचार सम्यक् ज्ञान, आगम-अध्ययन तथा साधना से ही संभव है। सूत्र और अर्थ का संबंध धागे और मोतियों के समान है। धागे के बिना जैसे मोती बिखर जाते हैं, वैसे ही सूत्रों के बिना शास्त्रों का वास्तविक अर्थ स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने बताया कि समय के साथ महापुरुषों ने नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीकाओं के माध्यम से आगम के गूढ़ तत्त्वों को सरल बनाया। आगम, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका का समन्वय पंचांगी' कहलाता है, जो साधक को तत्त्वज्ञान तक पहुँचाता है।

# व्रत, प्रत्याख्यान और धर्म आराधना ही आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है : जयतिलक मुनि

चेन्नई/दक्षिण भारत । यहां साहुकारपेट के एसएस जैन संघ के तत्वावधान में जैन भवन के प्रांगण में विराजित श्री पार्श्वचन्दजी म.सा. के शिष्य, श्री जयतिलक मुनिजी म.सा. 'लघु' ने गुरुवार को धर्मसभा को संबोधित करते हुए आत्मकल्याण, कर्म सिद्धांत तथा व्रत-प्रत्याख्यान के महत्व पर प्रेरणादायी प्रवचन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सांसारिक आत्मा अनंतकाल तक निगोद के जीव रूप में भटकती रही है। प्रबल पुण्य के उदय से आत्मा निगोद से बाहर निकलकर पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय तथा वनस्पतिकाय आदि योनियों में

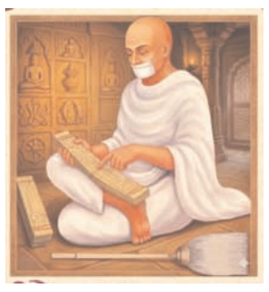

भ्रमण करती है। एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्यायों में जन्म-मरण का चक्र चलता रहता है और अनंत पुण्य के फलस्वरूप ही दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य भव प्राप्त होने के बाद भी आत्मा मोह, माया और विषय-विकारों के जाल में उलझी रहती है, जबकि जागृत आत्मा ही इन बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाती है। मुनिश्री ने कहा कि आत्मा पर बंधे हुए आठ कर्मों से पूर्णतः मुक्त होना अत्यंत कठिन कार्य है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को कर्मबंधन से मुक्त नहीं करा सकता। प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। पांचों इन्द्रियों के विषयों का त्याग, संयम, तप, जप और त्यागमय जीवन आत्मा को कर्मनिर्जरा की दिशा में अग्रसर करते हैं। कर्मों के जाल से मुक्त होकर ही आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है।

# दो दिवसीय आईसीईआर-आईडी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-2026 का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां एसआरएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र ने उभरते और पुन: उभरते संक्रामक रोगों पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीईआर-आईडी 2026) का आयोजन किया। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रतिरक्षा विज्ञान, टीकाकरण विज्ञान, विषाणु विज्ञान, प्रणाली जीव विज्ञान, ट्रांसलेशनल मेडिसिन और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सम्मेलन में मद्रास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस डॉ. एस.पी. त्यागराजन, अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय के विनशिप कैंसर संस्थान के प्रोफेसर रफीक सेकली, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिरक्षा, प्रत्यारोपण और संक्रमण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बाली पुलेंद्रन, स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मैरी लार्सन और भारत के पुणे स्थित आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) की पूर्व निदेशक और वैज्ञानिक डॉ. प्रिया अब्राहम को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस वैज्ञानिक सम्मेलन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर मिरको पायर्डिनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के येल विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रीति कुमार और संयुक्त राज्य अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विजयकुमार वेलू को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधान नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में प्रख्यात वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत किया गया और उभरती और पुन: उभरती संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए नवीन रणनीतियों का पता लगाया गया।

इसमें संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरों के खिलाफ वैश्विक तैयारियों को मजबूत करने में अंत:विषयक अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

महामारी की तैयारी, एचआईवी रोग जनन, ध्वसन विषाणु विज्ञान, श्लेष्मा प्रतिरक्षा, सटीक निदान, उभरते और पुन: उभरते संक्रामक रोग और वैश्विक स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों पर आठ वैज्ञानिक सत्रों में 30 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया।

# दोषों का त्याग और सद्गुणों का अंगीकार ही धर्म है : साध्वी प्रियरंजनाश्री

चेन्नई/दक्षिण भारत । यहां रिथर्डन रोड़ स्थित कुशल बाग में चातुर्मासार्थ विराजित साध्वीश्री प्रियरंजनाश्रीजी ने गुरुवार के प्रवचन में धर्म के वास्तविक स्वरूप का अत्यंत प्रभावशाली एवं तात्त्विक विवेचन करते हुए कहा कि धर्म का प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह भवन की नींव की भांति अदृश्य रहकर भी सम्पूर्ण जीवन को स्थिरता, शक्ति और दिशा प्रदान करता है। उत्तम कुल में जन्म, श्रेष्ठ संस्कार, सत्संग की प्राप्ति, स्वस्थ इन्द्रियां तथा अनुकूल जीवन-परिस्थितियां धर्माराधना से अर्जित पुण्य का ही प्रतिफल हैं। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा, प्रतिक्रमण अथवा मंदिर-गमन तक सीमित नहीं है। अपने दोषों, दुर्भावनाओं और दुर्गुणों का त्याग कर सद्गुणों को जीवन में अपनाना ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्माराधना के चार प्रमुख उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि माता-पिता से प्राप्त धार्मिक संस्कारों का संरक्षण, कर्मनिर्जरा एवं सद्गति की प्राप्ति, संकटों का निवारण तथा जीवन की पवित्रता-ये धर्म के मूल आधार हैं। अंजना सती और माता सीता के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने इन सिद्धांतों को अत्यंत सरल एवं मार्मिक ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि मंदिर वह पावन स्थान है, जहां जीव को कर्मनिर्जरा का सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होता है।

प्रवचन में छोटे से छोटे गुणभाव से भी प्रेमभाव रखना विषय का उल्लेख करते हुए साध्वीश्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के गुणों का बहुमान, हृदय से प्रशंसा और आहोभाव ही सच्चे गुणानुराग की पहचान है। ईर्ष्या मनुष्य के पतन का कारण बनती है, जबकि दूसरों के गुणों की प्रसन्नतापूर्वक सराहना कर्मनिर्जरा का श्रेष्ठ माध्यम है। उन्होंने पीठ-महापीठ तथा बाहु-सुभाऊ के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से गुणानुवाद, विनय और गुणग्राहिता की महिमा का सुंदर प्रतिपादन करते हुए सभी को गुणों के प्रति अनुराग विकसित करने की प्रेरणा दी।

# सनातन धर्म विद्यालय एसोसिएशन ने मनाया वार्षिक दिवस

चेन्नई/दक्षिण भारत। यहां 5 अगस्त को सनातन धर्म एसोसिएशन के तत्वावधान में संचालित अपने चारों विद्यालय का संयुक्त वार्षिकोत्सव दिवस नारद गनसभा के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर ईश वन्दना के साथ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ नाक्षी रमेश रहीं। जिनका पारम्परिक सम्मान आरके झंवर ने एवं केके माहेश्वरी ने स्मृतिचिन्ह प्रदान कर किया। संगठन के अध्यक्ष डॉ. आरके झंवर ने आगन्तुकों के स्वागत में स्वागत भाषण की भूमिका निभाई। संगठन के महासचिव केके महेश्वरी ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। चारों शिक्षा संस्थानों के शीर्षस्थ शिक्षक ने भी अपने-अपने शिक्षा संस्थान के वार्षिक उपलब्धियों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में संगठन के 105 वें वार्षिकोत्सव पर संगठन के कार्यों की सराहना की। मेधावी छात्र-छात्राओं को उपयोगी पुस्तकों, मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। एसएसडीवी के पत्राचारक एसपी बाहेती ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति और संस्कार की झलक दिखाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर श्रीगोपाल अग्रवाल, अशोक कुमार मूंदड़ा, विजयकुमार गोयल, आरसी डागा, एसएस दम्मानी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

# जीतो जॉब्स द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष मेगा रोजगार एवं सशक्तिकरण अभियान का सफल आयोजन

चेन्नई//दक्षिण भारत । समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानजनक आजीविका एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से जीतो चेन्नई चैप्टर द्वारा अपनी प्रमुख पहल जीतो जॉब्स के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष मेगा रोजगार एवं सशक्तिकरण अभियान का भव्य आयोजन किया गया। जीतो चेन्नई चैप्टर के चेयरमैन राजेश चंदन ने बताया कि यह आयोजन एक सामान्य जॉब फेयर नहीं था, बल्कि विशेष रूप से दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक अनूठी पहल थी। कार्यक्रम का उद्देश्य योग्य एवं प्रतिभाशाली दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऐसे नियोक्ताओं से जोड़ना था, जो समावेशी कार्य संस्कृति में विश्वास रखते हैं।

जीतो एपेक्स के संयुक्त कोषाध्यक्ष डी.के. जैन ने कहा कि जीतो जॉब्स का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने का अवसर मिलना चाहिए और इसी सोच को साकार करने के लिए यह विशेष रोजगार अभियान आयोजित किया गया। इस विशेष रोजगार मेले में 35 प्रतिष्ठित कंपनियों एवं औद्योगिक संस्थानों ने भाग लेकर विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थकेयर, सर्विस एवं प्रशासनिक सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इस मेले में 328 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा योग्य अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह आयोजन समाज में समावेशी रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम में एक विशेष आकर्षण 'मुक्ति' संस्था द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग वितरण समारोह रहा। 'मुक्ति' संस्था अब तक देशभर में 5 लाख से अधिक कृत्रिम अंग वितरित कर हजारों दिव्यांगजनों के जीवन में नई आशा का संचार कर चुकी है। इस अवसर पर जीतो चेन्नई की टीम के सहयोग से अनेक लाभार्थियों को कृत्रिम पैर, विशेष रूप से निर्मित कृत्रिम हाथ एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए।

# सरल हृदय में होता है धर्म का निवास : साध्वीश्री मंगलज्योति

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के वर्द्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ शांतिनगर के तत्वावधान में चातुर्मासार्थ विराजित साध्वीश्री मंगलज्योतिजी ने गुरुवार को अपने प्रवचन में कहा कि जीवन में सरल बनो। सरलता का गुण अपनाएं, यह आपके जीवन विकास का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी आत्मा में सरलता का गुण होना आवश्यक है।

सरल हृदय में ही धर्म का निवास होता है। सरल हृदय में ही धर्म ठहरता है। सीधे बनो और सिद्ध बनो। माया, अहंकार का त्याग करें। मायावी नहीं बनना है।

मायावी व्यक्ति आगे भव में नारी रूप में उत्पन्न होता है। अहंकार ज्ञान प्राप्ति में बाधक तत्व है। उन्होंने कहा कि क्षमावान व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है। जीवन में क्षमा और सरलता का गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को लोकप्रिय, प्रभावशाली बनाता है।

प्रारंभ में साध्वी ऋजु प्रज्ञाजी ने कहा कि आत्मा अनंत शक्तिमान है। हमारे अन्दर यह शक्ति है कि मैं आत्मा को कर्मों से अलग कर दूं।

ऐसा विश्वास और दृढ़ता साधनाशील साधक आत्मा के मन में होना चाहिए। देह विनाशी और हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। पुरुषार्थ द्वारा आत्मकल्याण संभव है। साध्वी ऋजुप्रज्ञाजी ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री छगनमल लुणावत ने किया। सहमंत्री नरेंद्र बेताला ने सबको धन्यवाद दिया।

# 'रीलस्टार्स' प्रतियोगिता' के माध्यम से जीतो महिलाओं ने दिए रचनात्मक और सामाजिक संदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) साउथ लेडीज़ विंग ने अपने मेंबरशिप कनेक्ट वर्टिकल प्रोग्राम के अंतर्गत रीलस्टार्स नामक एक अनूठी रील निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने सभी का स्वागत किया। मुख्य सचिव निधि पालरेचा ने प्रतिभागियों के उत्साह, समन्वय और टीम भावना की सराहना करते हुए कहा कि सदस्यता केवल संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने, यादगार अनुभव साझा करने और एक परिवार की तरह साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर है।

प्रतियोगिता में रीलों का मूल्यांकन रचनात्मकता, मौलिकता, अभिनय, प्रस्तुति, टीमवर्क, तकनीकी गुणवत्ता, सामाजिक संदेश की प्रासंगिकता, दर्शकों पर प्रभाव तथा समग्र प्रस्तुति के आधार पर किया गया।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.